शनिवार, 4 जुलाई 2026

आषाढ़, कृ.प., चतुर्थी, विक्रमीय संवत् 2083

मूल्य Rs. 4, (कोलकाता Rs. 3)

वर्ष : 21, संख्या : 211, पृष्ठ-8

कोलकाता

RNI No. WBHIN/2005/16483

www.bharatmitranews.com

भारतमित्र

प्रथम प्रकाशन 1878

राउंड 32 **फीफा विश्व कप 2026 (आज का मैच)** राउंड 16

- अर्जेंटिना बनाम कोवा वर्दे - 03.30 A.M
- कोलंबिया बनाम घाना - 07.00 A.M
- कनाडा बनाम मोरक्को - 10.30 A.M

बोजकोवा और नवारो तीसरे दौर में क्रेजिकोवा ने एंड्रीवा को किया बाहर

पेज-8

BHARATMITRA, KOLKATA, SATURDAY, 4 JULY 2026

पोस्ता हिंसा में मुख्य आरोपी चंदन चक्रवर्ती गिरफ्तार

कोलकाता, नि.सं: पोस्ता मर्चेंट एसोसिएशन के सचिव विश्वनाथ अग्रवाल के साथ हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने पहली सफलता हासिल की है। पुलिस ने चंदन चक्रवर्ती को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ जारी है, जिससे

बाकी आरोपितों की तलाश तेज

बाकी आरोपियों तक पहुँचने में मदद मिलेगी।

'गुड़िया' की तलाशः वीडियो में विश्वनाथ अग्रवाल पर थप्पड़ बरसाती हुई दिखाई दे रही महिला 'भारती' (उर्फ गुड़िया) पुलिस की रडार पर है। उसे पकड़ने के लिए कई ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

आरोपियों में खौफः मामले में नामजद होते ही कल तक सीना तानकर घूमने वाले सभी आरोपी फरार हो चुके हैं। पुलिस की कार्रवाई के डर से सभी ने अपने घर छोड़ दिए हैं।

पुलिस का सख्त रुखः प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दबंगई अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए इलाके में खुफिया जाल बिछाया गया है।

साजिशन बिखेरा गया बंगाल : सीएम

लोकतंत्र को फिर से खड़ा करना होगा

कोलकाता, नि.सः पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अब तक का सबसे तीखा राजनीतिक हमला बोला। नवनिर्वाचित विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बंगाल की स्थिति उतनी खराब नहीं हुई, जितनी पिछले वर्षों में हुई। उन्होंने दावा किया कि अब राज्य में लोकतांत्रिक संस्थाओं, विधानसभा की गरिमा और संसदीय परंपराओं को फिर से मजबूत करने का समय आ गया है।

दो दिवसीय प्रबोधन (ओरिएंटेशन) कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका उद्देश्य राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप करना नहीं, बल्कि नए विधायकों के सामने तथ्य रखना है ताकि वे लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसदीय परंपराओं को बेहतर ढंग से समझ सकें।

'पार्टी कार्यालयों से चलते थे फैसले'

मुख्यमंत्री ने वाममोर्चा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 34 वर्षों के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले विधानसभा के बजाय पार्टी कार्यालयों से लिए जाते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उसके बाद के 15 वर्षों में लोकतांत्रिक संस्थाएं और अधिक कमजोर हुईं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के नेता की मौजूदगी में वह राजनीतिक टिप्पणी को अधिक आगे नहीं बढ़ाना चाहते।

सभी विधायकों को मिलेगा बराबर सम्मान

शुभेंदु अधिकारी ने अपने विधायक और पूर्व विपक्ष के नेता के अनुभव साझा करते हुए कहा कि पहले विपक्षी विधायकों को पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता था। अब सरकार प्रशासनिक बैठकों, विकास योजनाओं और बजट चर्चा में सभी दलों के विधायकों को शामिल कर रही है ताकि लोकतांत्रिक भागीदारी मजबूत हो सके।

बंगाल के विकास का रखा विजन

मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के पास उद्योग, उच्च शिक्षा संस्थान, प्राकृतिक संसाधन और मजबूत परिवहन नेटवर्क जैसी सभी बुनियादी ताकतें मौजूद हैं। जरूरत केवल सुशासन और पारदर्शी प्रशासन की है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य को विकास और लोकतंत्र के नए दौर में ले जाया जाएगा।

विभाजन के इतिहास का भी किया जिक्र

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने 1947 के भारत विभाजन के समय बंगाल विधानसभा की ऐतिहासिक भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में हुए मतदान के बाद ही पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बना था और उस समय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके पक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

ओम बिरला ने किया उद्घाटन

नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित इस दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा सचिवालय के अंतर्गत पार्लियामेंटरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज (प्राइड) तथा पश्चिम बंगाल विधानसभा के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

क्या है संदेश?

मुख्यमंत्री का यह बयान केवल नए विधायकों के प्रशिक्षण तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पूर्ववर्ती सरकार पर राजनीतिक प्रहार और नई सरकार के शासन मॉडल का सार्वजनिक संदेश भी माना जा रहा है। इससे साफ संकेत मिला कि राज्य सरकार आने वाले समय में लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती, प्रशासनिक सुधार और राजनीतिक जवाबदेही को अपने प्रमुख एजेंडे के रूप में पेश करना चाहती है।

कोलकाता में ओम बिड़ला ने दी सीख, कहा

विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल जरूरी

कोलकाता, नि.सं। लोकतंत्र की गुणवत्ता केवल चुनाव जीतने से नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली और जवाबदेही से तय होती है। इसी सोच के साथ बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए शुक्रवार को कोलकाता के राजारहाट न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में दो दिवसीय प्रबोधन (ओरिएंटेशन) कार्यक्रम की शुरूआत हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया।

अपने संबोधन में ओम बिरला ने कहा कि एक विधायक केवल अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि पूरे राज्य की आकांक्षाओं और उम्मीदों का वाहक होता है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का अंतिम लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए।

बिरला ने नवनिर्वाचित विधायकों को सीखने और समझने की निरंतर इच्छा बनाए रखने की सलाह देते हुए कहा कि उन्हें सदन की कार्यवाही में अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए, अनुभवी सदस्यों के विचारों को सुनना चाहिए और संसदीय परंपराओं का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल तकनीक के दौर में जनप्रतिनिधियों को भी समय के साथ खुद को लगातार अपडेट रखना होगा।

'संवाद ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत'

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन संवाद की परंपरा और सदन की गरिमा हर परिस्थिति में बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ बहस और रचनात्मक चर्चा लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाती है।

विकसित बंगाल पर जोर

ओम बिरला ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए विकसित बंगाल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने सभी विधायकों से राज्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का आह्वान किया।

बंगाल की विरासत का किया उल्लेख

अपने संबोधन में बिरला ने बंगाल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बंगाल ने देश को आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन की नई दिशा दी। वंदे मातरम् के उद्घोष से स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा मिली और अब उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए बंगाल को विकास के नए शिखर तक पहुंचाना होगा।

इन नेताओं की रही मौजूदगी

प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश तथा देश के विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ सांसद भी मौजूद रहे।

मुख्य बातें

- **नवनिर्वाचित विधायकों के लिए दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम शुरू।**
- **ओम बिरला बोले- सीखने और नवाचार की ललक जरूरी।**
- **सदन की कार्यवाही और अनुभवी सदस्यों से सीखने की सलाह।**
- **अकऔर डिजिटल तकनीक के साथ खुद को अपडेट रखने पर जोर।**
- **विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल आवश्यक।**
- **लोकतंत्र में संवाद और सदन की गरिमा बनाए रखने का आह्वान।**

राज्य सरकार कानूनी पैनल में करेगी बड़ा बदलाव

कोलकाता, नि.सं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार राज्य के सरकारी अधिवक्ताओं और लोक अभियोजकों के पैनल में व्यापक बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार का उद्देश्य बाहरी वरिष्ठ अधिवक्ताओं पर निर्भरता कम करना और सरकारी मामलों की प्रभावी पैरवी के लिए अपने कानूनी तंत्र को मजबूत बनाना है, जिससे सरकारी खजाने पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ को भी कम किया जा सके।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के वर्तमान सरकारी अधिवक्ताओं और लोक अभियोजकों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता मामलों की अधिक प्रभावी और तथ्यपूर्ण पैरवी करें, ताकि भविष्य में महंगे बाहरी वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सेवाएं लेने की आवश्यकता कम हो।

बैठक में मुख्यमंत्री ने मौजूदा कानूनी पैनल की कमजोरियों की पहचान करने और आवश्यकता पड़ने पर उसमें व्यापक बदलाव करने की प्रक्रिया शुरू करने का भी सुझाव दिया। उनका मानना है कि राज्य के अपने अधिवक्ताओं की क्षमता बढ़ाकर सरकार कानूनी मामलों में बेहतर परिणाम हासिल कर सकती है।

बैठक में मौजूद एक लोक अभियोजक के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार के कार्यकाल में सरकारी मामलों में लगातार बाहरी वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त करना एक सामान्य प्रक्रिया बन गई थी, क्योंकि राज्य सरकार के पैनल के अधिवक्ताओं की पैरवी वाले कई मामलों में सरकार को अदालतों में लगातार पराजय का सामना करना पड़ा।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से कलकत्ता उच्च न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं के पैनल को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई बार सरकारी अधिवक्ताओं और लोक अभियोजकों को मामलों की सुनवाई के दौरान पुलिस तथा विभिन्न सरकारी विभागों से आवश्यक दस्तावेज और सूचनाएं समय पर नहीं मिल पाती हैं, जिससे प्रभावी पैरवी प्रभावित होती है।

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी सरकारी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि सरकारी अधिवक्ताओं को समय पर दस्तावेज और अन्य जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी विभाग से सहयोग नहीं मिलता है तो संबंधित अधिवक्ता सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

गुजरात में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आठ संदिग्ध गिरफ्तार

अहमदाबाद । गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) से कथित संबंध रखने और राज्य में संगठन का सक्रिय नेटवर्क खड़ा करने की साजिश रचने के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियां गुजरात और मध्य प्रदेश में की गईं। एटीएस के अनुसार, विस्तृत जांच के बाद गुरुवार को एटीएस पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धाराएं 13, 17, 18, 38 और 39 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धाराएं 148 और 61 के तहत मामला दर्ज किया गया। एटीएस अधिकारियों ने दावा किया कि गिरफ्तार सभी आठ आरोपी प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए हैं और राज्य में संगठन का सक्रिय नेटवर्क तैयार कर उसकी आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बनासकांठा जिले के पालनपुर शहर के भागल निवासी अहमद अब्दुल्ला गाजीवाला उर्फ अबू उबैदा (19), इब्राहिम मोहम्मद हुसैन घाघा उर्फ अबू हमजा (30), मुदस्सिर अब्दुल्ला गाजीवाला उर्फ अबू आया (22), पाटन जिले के सिद्धपुर स्थित खडियासणा की जामिया अबुल हसन मदरसा के जकारिया दुरानी मोहम्मद अम्मार घाघा उर्फ इब्न अम्मार उर्फ जकारिया पालनपुरी (21), उसी मदरसे के मुफ्ती फौजान इस्माइल दौवा उर्फ मुफ्ती साहब (40), मोहम्मद अमीन शेरा उर्फ अमीन पालनपुरी (21), नवसारी जिले के चिखली के अंभेटा स्थित जामिया रहमानिया खंभिया के मोहम्मद अब्दुल रहमान सावदी उर्फ मोहम्मद पालनपुरी उर्फ अबू उनीसा (22)

केंद्र ने इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक विज्ञापनों पर मेटा को किया तलब

नयी दिल्ली, एजेंसी। केन्द्र सरकार ने इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण सामग्री को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को लेकर मेटा को तलब किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने मंत्रालय के अधिकारियों को ऐसा करने के निर्देश दिए थे।

बाल यौन शोषण कंटेंट को बढ़ावा देने का आरोप

सूत्रों के अनुसार, मंत्री ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस गंभीर मामले में मेटा से जवाब तलब करें और यह स्पष्ट करें कि ऐसे विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर कैसे प्रसारित हुए। मंत्रालय इस पूरे मामले में कंपनी से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगेगा।

एक मीडिया जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंस्टाग्राम पर रेप वीडियो और चाइल्ड वीडियो जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर भुगतान किए गए विज्ञापन चलाए जा रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार, इन विज्ञापनों के जरिए उपयोगकर्ताओं को ऐसे टेलीग्राम चैनलों तक पहुंचाया जा रहा था, जहां कथित तौर पर बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) 99 रुपये जैसी कम कीमत पर बेची जा रही थी।

फिलहाल मेटा की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

बढ़ेगी रक्षा बलों की क्षमता, 52,000 करोड़ रुपये की खरीद को मंजूरी

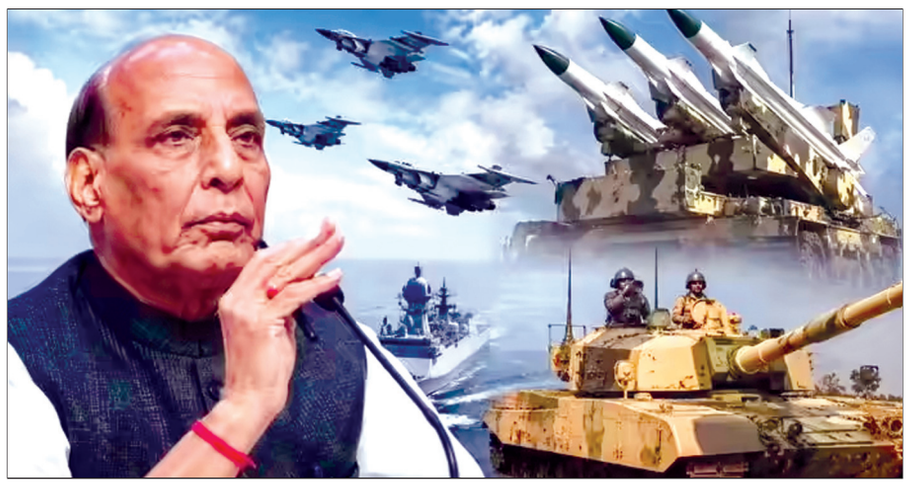

नयी दिल्ली, एजेंसी । देश के सशस्त्र सैन्य बलों को और अधिक आधुनिक व शक्तिशाली बनाने की दिशा में रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में लगभग 52,000 करोड़ रुपये की पूंजीगत रक्षा खरीद परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी (एओएन) प्रदान की गई। रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में स्वीकृत इन प्रस्तावों का उद्देश्य तीनों सेनाओं की युद्धक क्षमता, निगरानी व्यवस्था, वायु रक्षा और भविष्य के युद्धक्षेत्र की चुनौतियों से निपटने की तैयारी को मजबूत करना है। डीएसी ने भारतीय सेना के लिए कई महत्वपूर्ण प्रणालियों की खरीद को मंजूरी दी है। इनमें एंटी-ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली 'आकाश तरंग', मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, अत्यंत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली तथा जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली शामिल हैं। 'आकाश तरंग' प्रणाली सेना की अग्रिम तैनातियों और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को दुश्मन के ड्रोन हमलों से सुरक्षा प्रदान करेगी। यह प्रणाली ड्रोन का पता लगाने, उन्हें बाधित करने और निष्क्रिय करने में सक्षम है। वहीं, एंटी-टैंक मिसाइल से इन्फेंट्री की ताकत बढ़ेगी। मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली सेना की इन्फेंट्री टुकड़ियों को दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ अधिक प्रभावी बनाएगी। इससे अग्रिम मोर्चे पर सैनिकों की मारक क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और अत्यंत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन तथा अन्य हवाई खतरों को रोकने में अहम भूमिका निभाएंगी।

बहु-स्पेक्ट्रल सेंसर से लैस नई प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक बाधाओं के बावजूद प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगी। सक्रिय सुरक्षा प्रणाली टैंकों की ओर आने वाली मिसाइलों और रॉकेटों को बीच रास्ते में ही नष्ट कर सकेगी। इससे युद्धक्षेत्र में टैंकों के सुरक्षित बने रहने की क्षमता बढ़ेगी। भारतीय नौसेना के लिए बहु-प्रभावी समुद्री माइन, नौसैनिक जहाजों से संचालित मानवरहित हवाई प्रणाली तथा विद्युत प्रणोदन प्रणाली के लिए भूमि आधारित परीक्षण सुविधा स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। बहु-प्रभावी समुद्री माइन दुश्मन के युद्धपोतों और नौसैनिक अभियानों की स्वतंत्र आवाजाही को सीमित करने में मदद करेगी।

इससे समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा और मजबूत होगी। उन्नत सेंसरों से लैस नई मानवरहित हवाई प्रणाली नौसेना को समुद्र में दूर तक निगरानी रखने, संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और वास्तविक समय में जानकारी जुटाने में सहायता देगी। वहीं, भारतीय वायुसेना के लिए फिक्स्ड-विंग आधारित उच्च ऊंचाई स्यूडो सैटेलाइट प्रणाली सहित अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

प्रथम प्रकाशन 1878 भारतमित्र

भारत-बांग्लादेश के बीच ट्रेन यात्रा के दोबारा शुरू होने के संकेत

सिलीगुड़ी। लंबे इंतजार के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच एक बार फिर रेल सेवाएं शुरू होने की उम्मीद तेज हो गई है। ह्यमिताली एक्सप्रेसह्न के दोबारा पटरी पर लौटने के साथ-साथ ह्यबंधन और मैत्री एक्सप्रेसह्न के भी पुनः संचालन की संभावना जताई जा रही है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत और बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्रों के पूर्ण रूप से फिर से चालू होने से यह उम्मीद और मजबूत हुई है। सूत्रों के अनुसार, दोनों देशों के रेलवे अधिकारियों के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं, जिनमें ट्रेनों के रूट, ट्रैक की स्थिति और अन्य जरूरी बुनियादी ढांचे का जायजा लिया जा रहा है। यदि सभी तैयारियां समय पर पूरी हो जाती हैं, तो इसी महीने के भीतर ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो सकती हैं। उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि मिताली एक्सप्रेस के संचालन को लेकर अभी कोई निश्चित तारीख तय नहीं की गई है। उच्च स्तर के निर्देश पर ट्रैक और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति का आकलन किया जा रहा है और रिपोर्ट संबंधित विभागों को भेजी जा रही है। गौरतलब है कि, 2024 के जुलाई-अगस्त में बांग्लादेश में आंतरिक अशांति और राजनीतिक बदलाव के चलते सुरक्षा कारणों से भारत सरकार ने मैत्री, बंधन और मिताली तीनों यात्री ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। हालांकि, यात्री ट्रेनों के बंद रहने के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए मालगाड़ियों का संचालन जारी रखा गया। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन और हालात में सुधार के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में फिर से गर्माहट आई है। इसी के चलते यात्री ट्रेनों को दोबारा शुरू करने की दिशा में पहल तेज हुई है। बताया जा रहा है कि हाल ही में दोनों देशों के रेलवे अधिकारियों की दूसरी बैठक में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ट्रेनों के संचालन को लेकर प्रारंभिक सहमति बनी है।करीब दो साल बाद भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा जारी करना भी फिर से शुरू कर दिया है, जिससे पर्यटन और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक इलाज और अन्य जरूरतों के लिए भारत आते हैं, जो इन ट्रेनों के फिर से शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलते ही ट्रेनों के संचालन की तारीखों की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी।

रेल सेवाएं बहाल होने से भारत और बांग्लादेश के बीच न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि द्विपक्षीय व्यापार और स-ंस्कृतिक संबंध भी और मजबूत होंगे।उल्लेखनीय है कि, ह्यमिताली एक्सप्रेसह्न की शुरूआत 2022 में न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से ढाका कैंटोनमेंट के बीच हुई थी। ह्यबंधन एक्सप्रेसह्न 2017 में कोलकाता से खुलना के बीच शुरू हुई, जबकि भारत और बांग्लादेश के बीच पहली यात्री ट्रेन ह्यमैत्री एक्सप्रेसह्न 2008 में कोलकाता और ढाका के बीच शुरू की गई थी।

अन्नपूर्णा भंडार की राशि नहीं मिलने पर दासपुर में पंचायत कार्यालय घेराव

पश्चिम मेदिनीपुर । जिले के दासपुर क्षेत्र अंतर्गत पांचबेड़िया ग्राम पंचायत कार्यालय में शुक्रवार को अन्नपूर्णा भंडार योजना की राशि खातों में जमा नहीं होने से नाराज महिलाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के दौरान पंचायत कार्यालय का घेराव कर महिलाओं ने जमकर हंगामा किया।

जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता महिलाओं का आरोप है कि योजना के तहत मिलने वाली राशि के लिए दो महीने से अधिक समय पहले सभी जरूरी प्रक्रिया और दस्तावेज जमा कर दिए गए थे। इसके बावजूद अब तक उनके बैंक खातों में अन्नपूर्णा भंडार योजना की राशि नहीं पहुंची। देर होने से नाराज महिलाओं का गुस्सा शुक्रवार को फूट पड़ा।

आक्रोशित महिलाएं बड़ी संख्या में पांचबेड़िया ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचीं और कार्यालय को घेरकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान काफी देर तक शोर-शराबा और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। सूचना मिलने पर दासपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रही महिलाओं से बातचीत कर मामला शांत कराया। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।

आधिकारियो का कहना है कि योजना की राशि वितरण में हो रही देरी के कारण लाभार्थियों में लगातार असंतोष बढ़ रहा है।

भू माफियाओं पर पुलिस का बड़ा एक्शन, तीन गिरफ्तार

सिलीगुड़ी । माटीगाड़ा इलाके में लंबे समय से चल रहे अवैध जमीन कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन कथित भू माफियाओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान रिंकू सिंह, राजेश उरांव और पंकज तामांग के रूप में हुई है। यह कार्रवाई सांसद राजू बिष्ट के निर्देश के बाद तेज किए गए अभियान के तहत की गई है। जानकारी के अनुसार, माटीगाड़ा क्षेत्र में काफी समय से जमीन पर अवैध कब्जा कर उसे गैरकानूनी तरीके से बेचने की शिकायतें सामने आ रही थी। स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों की ओर से बार-बार इस मुद्दे को उठाया गया था। आरोप था कि इलाके में सक्रिय भूमि माफिया गिरोह आम लोगों को ठगने के साथ-साथ जमीन से जुड़े विवादों को भी बढ़ावा दे रहे थे। भाजपा ने आरोप लगाया था कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान भूमि माफियाओं का प्रभाव काफी बढ़ गया था, जिससे आम लोगों में डर का माहौल बन गया था। स्थिति ऐसी हो गई थी कि माटीगाड़ा ब्लॉक में लोग जमीन खरीदने से भी कतराने लगे थे।

सुरक्षा को लेकर चिंतित घाटाल नगर पालिका के कर्मचारी

घाटाल । पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के घाटाल नगर क्षेत्र में अन्नपूर्णा योजना की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में नहीं पहुंचने को लेकर लगातार हो रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच घाटाल म्युनिसिपालिटी के कर्मचारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी को लेकर गुरुवार शाम को नगरपालिका कर्मियों ने सुरक्षा की मांग करते हुए कार्यालय परिसर के बाहर बैठकर काम किया। हालांकि कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि यह कोई हड़ताल या धरना-प्रदर्शन नहीं है। नगरपालिका कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से अन्नपूर्णा योजना की राशि लाभार्थियों के खातों में जमा नहीं होने से नाराज लोग प्रतिदिन कार्यालय पहुंचकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे कार्यालय के सामान्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। नगरपालिका के हेड क्लर्क शिशिर पड़ेन ने बताया कि हाल ही में लगभग 20 से 25 असामाजिक तत्व कार्यालय में घुस आए और विभिन्न विभागों में जाकर कामकाज में बाधा पहुंचाई। आरोप है कि इस दौरान महिला कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया, जिससे कर्मचारियों के बीच भय का माहौल बन गया है। उन्होंने कहा कि यह किसी प्रकार का कार्य बहिष्कार या धरना नहीं है। सभी कर्मचारी कार्यालय के बाहर सामूहिक रूप से बैठकर सरकारी कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र सहित अन्य आवश्यक नागरिक सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कर्मचारियों के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक विभाग में तीन से चार कर्मचारी तैनात रहते हैं।

हथियार के साथ तृणमूल पूर्व छात्र नेता की वायरल तस्वीर से मचा हड़कंप

मालदा । सोशल मीडिया पर हथियार के साथ एक पूर्व तृणमूल छात्र परिषद नेता की तस्वीर शुक्रवार को वायरल होने के बाद जिले के सामसी और रतुआ इलाके में राजनीतिक तनाव फैल गया है। वायरल तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की पहचान रतुआ निवासी शेख रियाजुल के रूप में की जा रही है। बताया जा रहा है कि वह पहले सामसी कॉलेज में तृणमूल छात्र परिषद के यूनिट अध्यक्ष रह चुके है। हालांकि, इस वायरल तस्वीर की सत्यता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। इस घटना को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। भाजपा के उत्तर मालदा जिला महासचिव अभिषेक सिंघानिया ने कहा कि एक पूर्व छात्र नेता के हाथ में हथियार होना बेहद चिंताजनक है। हम निष्पक्ष जांच और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। आरोपित शेख रियाजुल से संपर्क करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन उनका मोबाइल फोन बंद होने के कारण कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। रतुआ थाने की पुलिस ने बताया कि वायरल पोस्ट उनके संज्ञान में है। तस्वीर की सत्यता के साथ-साथ पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तस्वीर सामने आने के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस बीच मालदा जिला तृणमूल छात्र परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रसून राय ने कहा कि शेख रियाजुल पहले सामसी कॉलेज के यूनिट अध्यक्ष थे, लेकिन वर्तमान में कोई यूनिट कमेटी नहीं है। मैंने भी सोशल मीडिया पर यह तस्वीर देखी है।

आसनसोल मंडल में नालियों की साफ-सफाई अभियान

आसनसोल । पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने मॉनसून की सालाना तैयारियों के तहत मंडल की कई जगहों पर मशीनों से नालियों की सफाई और गाद निकालने (डीसिल्टिंग) का विशेष अभियान शुरू किया है। यह काम पर्यावरण और हाउसकीपिंग प्रबंधन (ईएनएचएम) विभाग द्वारा किया जा रहा है ताकि मॉनसून के मौसम में रेलवे कॉलोनियों और कार्य क्षेत्रों में पानी की निकासी ठीक से हो सके, जल-जमाव को रोका जा सके और आसपास का माहौल साफ-सुथरा और स्वच्छ रखा जा सके। इस अभियान के तहत, आसनसोल और अंडाल में मुख्य नालियों और जल निकासी चैनलों की अच्छी तरह से सफाई और गाद निकालने का काम किया जा रहा है, ताकि बारिश का पानी आसानी से बह सके और भारी बारिश के दौरान जल निकासी व्यवस्था ठीक से काम कर सके। मॉनसून से पहले मंडल में जल निकासी की तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए दुगार्पुर स्टील एक्सचेंज यार्ड, रानीगंज, काजोरग्राम, चिनपाई, दुबराजपुर, दुगार्पुर, जसीडीह और मधुपुर जैसी प्रमुख रेलवे जगहों पर भी इसी तरह सफाई का काम किया जा रहा है। इस ऑपरेशन में नालियों से जमा गाद, ठोस कचरा और अन्य रुक-ावटों को हटाया जा रहा है। ईएनएचएम विभाग के अधिकारी और कर्मचारी काम को व्यवस्थित और समय पर पूरा करने के लिए बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।

कोयला खनन क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देंगे ईसीएल एवं एनआईटी दुगार्पुर

सांकतोड़िया/दुगार्पुर > ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), दुगार्पुर के सहयोग से अपने अधिकारियों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एवं मशीन लर्निंग (एमएल) विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 03 जुलाई, 2026 को सिटी रेजीडेंसी, दुगार्पुर में किया। कार्यक्रम का स्वागत एवं परिचय प्रो. अरविंद चौबे, निदेशक, एनआईटी दुगार्पुर द्वारा किया गया । उन्होंने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति को गति प्रदान करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, उभरती प्रौद्योगिकियों में दक्षता विकसित करने हेतु उद्योग एवं शिक्षण संस्थानों के मध्य सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया । तकनीकी सत्रों का शुभारम्भ डॉ. सुब्रत नंदी, पीएच.डी. (आईआईटी खड़गपुर) के व्याख्यान से हुआ । उन्होंने प्रतिभागियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग की मूलभूत अवधारणाओं से परिचित कराया तथा औद्योगिक अनुप्रयोगों में इनके बढ़ते महत्व पर विस्तृत जानकारी प्रदान की । दोपहर बाद एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया । जिसमें प्रतिभागियों ने विषय विशेषज्ञों के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया । इसके पश्चात डॉ. सर्वानन चंद्रन, एसोसिएट प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग, एनआईटी दुगार्पुर ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर विस्तृत व्याख्यान दिया । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में गुंजन कुमार सिन्हा, निदेशक (कार्मिक), ईसीएल तथा गिरीश गोपीनाथन नायर, निदेशक (तकनीकी), ईसीएल की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का समापन डॉ. सर्वानन चंद्रन

कैट ने की पोस्ता बाजार में व्यवसायी पर हमले की निंदा

आसनसोल । कॉनफि डरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स (केट) के नेशनल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुभाष चंद्र अग्रवाला ने कहा कि पोस्ता बाजार में व्यवसायी पर हमले की निंदा की है।

2 जुलाई 2026 को दोपहर लगभग 1:30 बजे,पोस्ता बाजार मर्चेंट्स एसोसिएशन के ही कुछ बेईमान व्यापारियों (जो एसोसिएशन पर अवैध रूप से नियंत्रण करना चाहते हैं) द्वारा उकसाए और बहकाए गए दो महिलाओं सहित लगभग 50 असामाजिक तत्व ₹द पोस्ता बाजार मर्चेंट्स एसोसिएशन₹ के कार्यालय में घुस गए, और उन्होंने फंड की हेराफेरी के निराधार आरोप लगाते हुए एसोसिएशन के महासचिव बिश्वनाथ अगरवाला को गाली दी और उन पर हमला कर दिया । कुछ बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है । देश के नौ करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला देश का सबसे बड़ा व्यापारी संगठन, 'कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स' (कैट) के नेशनल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, सुभाष अग्रवाला ने कहा कि कैट का पूरा परिवार पोस्ता बाजार मर्चेंट्स एसोसिएशन के महासचिव बिश्वनाथ अग्रवाल पर हुए क्रूर हमले की कड़ी निंदा करता है ।

दुगार्पुर ताप विद्युत केंद्र में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक

दुगार्पुर । दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के दुगार्पुर ताप विद्युत केंद्र (डीटीपीएस) में राजभाषा कार्यान्वयन समिति।

की अप्रैलझजून 2026 तिमाही बैठक शुक्रवार को परियोजना प्रधान एवं मुख्य महाप्रबंधक श्री एन. वी. रमना की अध्यक्षता में आयोजित की गई । अध्यक्षीय संबोधन में रमना ने राजभाषा के विकास हेतु अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए।उन्होंने कहा कि हिन्दी अत्यंत सरल, सहज और व्यवहारिक भाषा है। बैठक में विभिन्न विभागों के अनुभागीय प्रमुख उपस्थित रहे। इनमें उप महाप्रबंधक बासुदेव मंडल, वरिष्ठ प्रबंधक दिग्विजय राय, वरिष्ठ प्रबंधक पलाश राय, वरिष्ठ प्रबंधक कुमुद रंजन झा तथा वरिष्ठ प्रबंधक श्री संजय सरदार सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक (राजभाषा) डॉ. पिंकी जायसवाल ने किया, जबकि कनिष्ठ हिन्दी अधिकारी मधुमिता साहा ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान किया।

आरटीपीएस सीएसआर द्वारा रक्तदान शिविर

पंचेत । डीवीसी के स्थापना दिवस से पूर्व आरटीपीएस सीएस-ाआर द्वारा आरटीपीएस हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर लगाया गया इस दौरान रक्तदान शिविर का विधिवत उद्घाटन अविजित घोष जीएम एचओपी आरटीपीएस ने दीप प्रज्वलित कर किया ।

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आरटीपीएस की तरफ से इंसान की जान बचाने के लिए यह बहुत जरूरी तथा लाभकारी पहल है । उन्होंने सभी से मुश्किल समय में जान बचाने के नेक काम के लिए रक्तदान दान करने की अपील की । इस दौरान कुल 36 लोगों ने शि-विर में रक्तदान किया ।

इस अवसर पर निवेदानंद मंडल, (एसआर जीएम सिविल), अजय कुमार (एस आर जीएम प्रोजेक्ट), गोपा चक्रवर्ती (डीजीएम सीएसआर), बिजॉय बेहरा (डीजीएम प्रोजेक्ट), तन्जॉय चक्रवर्ती (एस आर मैनेजर हेल्थ), सोमनाथ दत्ता (एस आर मैनेजर एनवायरनमेंट) और डीवीसी के कई अन्य कर्मचारी मौजूद थे ।

मोहम्मद सलीम केंद्र और राज्य सरकार पर कटाक्ष

मिड-डे मील- बुलडोजर नीति पर सवाल

सिलीगुड़ी । उत्तर बंगाल में मुख्यमंत्री के दौरे के बीच सिलीगुड़ी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकार पर कटाक्ष किया है।

उन्होंने देश की खराब होती आर्थिक स्थिति और बढ़ती महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आम जनता पर बोझ डालकर बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत और रोजमर्रा की वस्तुओं के बढ़ते दामों पर गहरी चिंता जताई।

मोहम्मद सलीम ने मिड-डे मील में सोयाबीन के उपयोग को लेकर भी केंद्र सरकार की नीति की कड़ी आलोचना की। साथ ही, देशभर में चल रही ह्यबुलडोजर नीतिह्न पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर मेहनतकश लोगों की आजीविका छीनी जा रही है।

उन्होंने उत्तर बंगाल के बंद पड़े चाय बागानों को जल्द खोलने की मांग करते हुए कहा कि इससे हजारों श्रमिकों को रोजगार मिल सकेगा। सलीम ने सरकार से इस दिशा में तत्काल ठोस कदम उठाने की अपील की।

हालांकि, उन्होंने नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के उत्तर बंगाल दौरे को सकारात्मक कदम बताया और कहा कि आम लोगों की समस्याएं सुनने के लिए नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा किया जाना चाहिए।

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके दौरे अधिकतर औपचारिक ही रहे उससे कोई ठोस परिणाम नहीं निकला।

सलीम ने शिक्षा क्षेत्र में कथित भ्रष्टाचार समेत तृणमूल शासनकाल के विभिन्न मामलों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही।

सुप्रभात

4 जुलाई 2026, शनिवार , वर्ष मन्मथ (2083) आषाढ़, कृ.प., चतुर्थी सूर्योदय 06:17 ,सूर्यास्त 17.23

आज का राशिफल

मेष आर्थिक स्थिति में सुधार शॉर्टकट से नहीं, बल्कि आपकी सोची-समझी प्लानिंग से ही आएगा।

वृषभ दिन अपनी पुरानी बचत और आगे के निवेशों को एक बार फिर से जांचने के लिए बहुत अच्छा है।

मिथुन कोई भी नया आर्थिक वादा करने से पहले अपनी पुरानी जिम्मेदारियों को अच्छे से देख लें।

कर्क पेशेवर विकास के अवसर है। आर्थिक स्थिति को लगातार मजबूती मिलेगी।

सिंह आज जोखिम भरे कामों से पूरी तरह दूर रहें और अपने पास मौजूद धन को सुरक्षित रखने पर ध्यान दें।

कन्या दिन पूरा साथ दे रहा है। आप अपनी बचत को बढ़ाने के कुछ अच्छे रास्ते तलाशने में सफल रहेंगे।

तुला आज घर-परिवार की जरूरतों से जुड़े कुछ खर्चे आज सामने आ सकते हैं।

वृश्चिक पैसों को लेकर आपका नियम से चलना आज आपके हक में रहेगा।

धनु नया निवेश की तरफ कदम बढ़ाने से पहले अपनी पुरानी योजनाओं को अच्छे से परख लें।

मकर बजट को नए सिरे से व्यवस्थित करने और फालतू खर्चों को कम करने में सफल रहेंगे।

कुंभ आज किसी भी तरह के दबाव में आकर धन से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय न लें।

मीन आज सही प्लानिंग के जरिए आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे अच्छा सुधार देखने को मिलेगा।

मोहन बागान बनाम ईस्ट बंगाल से होगा 135वें डूरंड कप का आगाज, शुभारंभ 25 जुलाई से

कोलकाता, (नि.सं.)। एशिया के सबसे पुराने और दुनिया के तीसरे सबसे पुराने फुटबॉल टूनार्मेंट 135वें इंडियन ऑयल डूरंड कप का शुभारंभ 25 जुलाई को ऐतिहासिक कोलकाता डर्बी से होगा। उद्घाटन मुकाबले में रिकॉर्ड 17 बार की चैंपियन मोहन बागान सुपर जायंट का सामना 16 बार की विजेता ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब से कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में होगा। डूरंड कप आयोजन समिति ने शुक्रवार को प्रतियोगिता का पूरा कार्यक्रम जारी किया।

मूल रूप से इंडियन आर्मी से संबंधित इस टूनार्मेंट में इस वर्ष में 24 टीमें भाग लेंगी, जिन्हें 6 समूहों में बांटा गया है। प्रतियोगिता का आयोजन 25 जुलाई से 23 अगस्त तक कोलकाता, रांची, इंफाल, शिलांग और गुवाहाटी में किया जाएगा। इसमें देश के प्रमुख क्लबों, तीनों सेनाओं की टीमों, उभरते फुटबॉल क्लबों तथा अंतरराष्ट्रीय टीमों की भागीदारी रहेगी।

टूनार्मेंट का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि इसकी सीधी प्रसारण सेवा सोनीलिव पर उपलब्ध रहेगी।

कोलकाता वर्ष 2019 से डूरंड कप का स्थायी मेजबान रहा है। इस बार यहां समूह ए और बी के मुकाबलों के साथ उद्घाटन मैच, दो क्वार्टर फाइनल, पहला सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा।

समूह ए में मोहन बागान सुपर जायंट, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब, साउथ यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रोटेक्टर्स शामिल हैं। इस समूह का सबसे बड़ा आकर्षण 25 जुलाई का कोलकाता डर्बी होगा। समूह चरण का अंतिम मुकाबला 10 अगस्त को मोहन बागान सुपर जायंट और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रोटेक्टर्स के बीच खेला जाएगा।

समूह बी में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, भारतीय थल सेना फुटबॉल टीम, बागपत फुटबॉल क्लब और पहली बार भाग ले रही समलेश्वरी स्पोर्टिंग को स्थान मिला है। इस समूह का पहला मुकाबला 26 जुलाई को भारतीय थल सेना फुटबॉल टीम और समलेश्वरी स्पोर्टिंग के बीच होगा, जबकि अंतिम मुकाबला 12 अगस्त को मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब और भारतीय थल सेना फुटबॉल टीम के बीच खेला जाएगा।

पहली बार मेजबानी कर रहे रांची में समूह सी के सभी मुकाबले बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होंगे। इस समूह में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब, स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली, भारतीय वायु सेना फुटबॉल टीम तथा श्रीलंका की सशस्त्र बलों की टीम डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब शामिल हैं। पहला मुकाबला 26 जुलाई और अंतिम मुकाबला 13 अगस्त को होगा।

इंफाल में समूह डी के मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें ट्राऊ फुटबॉल क्लब, नेरोका फुटबॉल क्लब, फुटबॉल क्लब रेंगदाई और भारतीय नौसेना फुटबॉल टीम शामिल हैं। प्रतियोगिता की शुरूआत 28 जुलाई को ट्राऊ और नेरोका के बीच मणिपुर डर्बी से होगी।

शिलांग में समूह ई के मुकाबलों में शिलांग लाजोंग फुटबॉल क्लब, लैंगस्निंग फुटबॉल क्लब, नोंगकसेह स्पोर्ट्स सोशल एंड कल्चरल क्लब तथा मुंबई फुटबॉल क्लब आमने-सामने होंगे। यहां पहला मुकाबला 31 जुलाई को खेला जाएगा, जबकि 13 अगस्त को शिलांग डर्बी इस समूह का सबसे बड़ा आकर्षण होगी।

गुवाहाटी में समूह एफ में लगातार दो बार की मौजूदा चैंपियन नॉर्थईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, बोडोलैंड फुटबॉल क्लब, फुटबॉल क्लब वन और कार्बी आंगलोंग मॉर्निंग स्टार फुटबॉल क्लब शामिल हैं। यहां मुकाबलों की शुरूआत 01 अगस्त से होगी।

समूह चरण समाप्त होने के बाद 6 समूह विजेता और 2 सर्वश्रेष्ठ उपविजेता टीमें नॉकआउट चरण में पहुंचेंगी। क्वार्टर फाइनल 16 और 17 अगस्त, सेमीफाइनल 19 और 20 अगस्त, जबकि फाइनल 23 अगस्त को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेला जाएगा।

उल्लेखनीय है कि, डूरंड कप की शुरूआत 1888 में शिमला में हुई थी। बाद में यह प्रतियोगिता 1940 में नई दिल्ली स्थानांतरित हुई और 2019 से पूर्वी कमान के संरक्षण में कोलकाता में आयोजित की जा रही है। विजेता टीम को डूरंड कप, शिमला ट्रॉफी और राष्ट्रपति कप प्रदान किए जाते हैं।

अन्नपूर्णा भंडार योजना के भुगतान में गड़बड़ी से तमतमाए मंत्री भास्कर

हुगली, (नि.सं.)। पश्चिम बंगाल सरकार के राज्य मंत्री एवं श्रीरामपुर के विधायक भास्कर भट्टाचार्य ने गुरुवार रात रिषड़ा और श्रीरामपुर नगरपालिका क्षेत्रों में अन्नपूर्णा भंडार योजना के लाभार्थियों को भुगतान नहीं मिलने के मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिला है और इसके लिए संबंधित नगरपालिका प्रशासन को जवाबदेही तय करनी होगी।

मंत्री ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि रिषड़ा और श्रीरामपुर नगरपालिका क्षेत्र की अनेक महिलाओं के बैंक खातों में अन्नपूर्णा भंडार योजना की राशि नहीं पहुंची है। उन्होंने आरोप लगाया कि आवेदन प्रक्रिया में नगरपालिका की ओर से लापरवाही बरती गई और लाभार्थियों को आवेदन की कोई रसीद (रिसिप्ट) भी नहीं दी गई। ऐसे में आवेदन पत्रों का क्या हुआ, इसकी पूरी जिम्मेदारी नगरपालिका और उसके चेयरमैन को लेनी होगी।

नगरपालिका को ठहराया जिम्मेदार

भास्कर भट्टाचार्य ने कहा, ₹यदि नगरपालिका इस समस्या का समाधान नहीं कर पाती है, तो हम हर संभव तरीके से लाभार्थी महिलाओं को उनका अधिकार दिलाएंगे। यह सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी संबंधित नगरपालिका प्रशासन को उठानी होगी और लापरवाही के परिणाम भी उन्हें ही भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि पहले लोग अपनी समस्याएं खुलकर नहीं बता पाते थे, लेकिन अब आम नागरिक बिना किसी डर के अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कहीं कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है, तो राज्य सरकार इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रिषड़ा नगरपालिका के चेयरमैन के खिलाफ दर्ज पुलिस शिकायत का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि अब मामले की जांच पुलिस कर रही है। उन्होंने कहा, ₹पुलिस यदि कानून के अनुसार उचित कार्रवाई नहीं करती है, तो हम आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। जो भी कदम उठाया जाएगा, वह पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा।₹

मंत्री के इस बयान के बाद रिषड़ा और श्रीरामपुर नगरपालिका क्षेत्रों में अन्नपूर्णा भंडार योजना के क्रियान्वयन और नगरपालिका प्रशासन की भूमिका को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है।

रिसड़ा नगरपालिका में भाजपा का प्रदर्शन, विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन

हुगली, (नि.सं.)। रिसड़ा नगरपालिका क्षेत्र की विभिन्न नागरिक समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के श्रीरामपुर मंडल-4 और मंडल-5 की ओर से शुक्रवार अपराह्न रिषड़ा नगरपालिका में प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया।

कार्यक्रम की शुरूआत नगरपालिका के मुख्य प्रवेश द्वार पर भाजपा कार्यकताओं के एकत्र होने के साथ हुई। इस दौरान पार्टी नेताओं ने उपस्थित कार्यकताओं को संबोधित करते हुए नगर की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान की आवश्यकता पर अपनी बात रखी। इसके बाद भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल नगरपालिका के अधिकारियों से मिला और विभिन्न मांगों पर चर्चा करने के बाद उन्हें ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल में भाजपा श्रीरामपुर मंडल-4 के अध्यक्ष संतोष सिंह, पार्षद शशि सिंह झा, पार्षद मनोज सिंह, अजय सिंह, विजय उपाध्याय, प्रिंस चौबे, राकेश सिंह तथा भाजयुमो मंडल-4 के अध्यक्ष संतोष मंडल सहित अन्य नेता शामिल थे।

भाजपा नेताओं के अनुसार ज्ञापन में जल निकासी व्यवस्था में सुधार, शहर की सफाई, नालों की नियमित सफाई, अतिक्रमण हटाने, नगरपालिका में कथित आर्थिक अनियमितताओं की जांच कराने समेत कई जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं।

भाजपा पार्षद शशि सिंह झा ने बताया कि नगरवासियों की लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका के अधिकारियों ने सभी मांगों को गंभीरता से सुना, उन्हें अभिलेख में दर्ज किया तथा शीघ्र आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

नवद्वीप में सुपारी कारोबारी के घर ईडी की छापेमारी

कोलकाता, (नि.सं.)। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के नवद्वीप में शुक्रवार तड़के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक सुपारी कारोबारी के आवास पर छापेमारी की। यह कार्रवाई नवद्वीप के मणिपुर इलाके में रहने वाले कारोबारी अशोक अधिकारी के दो आवासों पर की गई। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह लगभग 5 बजे ईडी के अधिकारी 5 वाहनों के काफिले के साथ कारोबारी के घर पहुंचे और तलाशी अभियान शुरू किया। सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में की जा रही है। कारोबारी के पुत्र ने भी बताया कि ईडी की कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है।बताया जा रहा है कि अशोक अधिकारी का सुपारी का कारोबार केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि असम, त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी फैला हुआ है। इसी कारोबारी गतिविधि से जुड़े वित्तीय लेनदेन और दस्तावेजों की जांच के लिए ईडी की टीम दोनों आवासों पर पहुंची। छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारी घर के भीतर मौजूद दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड, बैंक लेनदेन तथा अन्य महत्वपूर्ण कागजात की गहन जांच में जुटे रहे। खबर लिखे जाने तक तलाशी अभियान जारी था ।

भूमि अभिलेख और प्लॉट की जानकारी अब मुफ्त में मिलेगी

कोलकाता, (नि.सं.)। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य में खतियान (भूमि अधिकार अभिलेख) और जमीन के प्लॉट संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले लिया जाने वाला आवेदन शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने एक्स पर जारी अपने संदेश में कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नागरिक सेवाएं पारदर्शी, झंझटमुक्त और सभी लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हों। इसी उद्देश्य से पूर्ववर्ती सरकार के समय भूमि अभिलेखों और प्लॉट संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए वसूला जाने वाला आवेदन शुल्क अब औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने आवेदन शुल्क समाप्त करने की घोषणा

उन्होंने बताया कि अब राज्य के नागरिक बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन अपने खतियान और जमीन के प्लॉट की जानकारी की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए किसी प्रकार का आवेदन शुल्क या प्रमाणीकरण शुल्क नहीं देना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से राज्यभर के सभी भूमि मालिकों को सीधा लाभ मिलेगा, विशेष रूप से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें अपनी जमीन से संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए किसी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से आसानी से पूरी की जा सकेगी।उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य भूमि संबंधी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और नागरिकों के अनुकूल बनाना है, ताकि लोगों को आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि आपकी जमीन, आपका अधिकार और आपकी जानकारी अब केवल एक क्लिक की दूरी पर है।सरकार का मानना है कि इस पहल से भूमि अभिलेखों तक लोगों की पहुंच और अधिक आसान होगी तथा डिजिटल प्रशासन को भी मजबूती मिलेगी।

घुटियारी शरीफ में पंचायत प्रधान से पूछताछ में मिले चार और हथियार

दक्षिण 24 परगना, (नि.सं.)। जिले के घुटियारी शरीफ इलाके में गिरफ्तार पंचायत प्रधान से पूछताछ के बाद पुलिस ने चार और आग्नेयास्त्र बरामद किए हैं। कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस संचालित नारायणपुर पंचायत के प्रधान सलाउद्दीन सरदार को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस हिरासत में उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ के दौरान उन्होंने कुछ अहम जानकारियां दीं।पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर गुरुवार रात नारायणपुर क्षेत्र के बनमालीपुर आदर्श संघ क्लब के पास तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान एक पेड़ के नीचे झाड़ियों में सफेद बोरियों में छिपाकर रखे गए चार एकनली बंदूक बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दबाव में सलाउद्दीन सरदार खुद उस स्थान पर पहुंचे और हथियार छिपाने की जगह दिखाई। इसके बाद पुलिस ने वहां से चार बंदूक बरामद कर लिए। स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली तृणमूल नेता और पंचायत प्रधान की निशानदेही पर बार-बार हथियार मिलने की घटना से नारायणपुर इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस पूरे मामले की आगे जांच कर रही है।

पुलिस से दुर्व्यवहार के आरोप में पेश हुईं पूर्व सांसद अपरूपा पोद्दार

हुगली, (नि.सं.)। तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद अपुरूपा पोद्दार शुक्रवार को श्रीरामपुर थाने में पुलिस के समक्ष पेश हुईं। उनके पति की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने उन्हें लगातार तीसरे दिन तलब किया था।

बताया गया कि इससे पहले बुधवार और गुरुवार को भी पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह थाने नहीं पहुंची थीं। शुक्रवार को दोपहर करीब 12 बजे वह श्रीरामपुर थाने पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने अधिवक्ता का परिधान पहन रखा था।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले उनके पति की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के साथ कथित दुर्व्यवहार और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोपों को लेकर श्रीरामपुर थाना पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। शुक्रवार को उनकी उपस्थिति के बाद पुलिस मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है।

आवाज का नमूना देने के मामले में अभिषेक को नहीं मिली तत्काल राहत

कोलकाता, (नि.सं.)। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को उनकी आवाज का नमूना लेने के मामले में शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय से तत्काल राहत नहीं मिली। न्यायालय ने मामले की तत्काल सुनवाई की उनकी मांग खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि मंगलवार से पहले इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं होगी। अदालत ने निर्देश दिया कि अभिषेक को मंगलवार को दोबारा पीठ का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित करना होगा, जिसके बाद शीघ्र सुनवाई के अनुरोध पर विचार किया जाएगा।

शुक्रवार को अभिषेक बनर्जी के अधिवक्ता सब्यसाची बंद्योपाध्याय और अयन भट्टाचार्य ने न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग रखी। उन्होंने दलील दी कि पहले की पीठ इस मामले में सुनवाई का संकेत दे चुकी है, इसलिए मामले की शीघ्र सुनवाई आवश्यक है। हालांकि, न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया कि मंगलवार से पहले किसी भी अर्जी पर सुनवाई संभव नहीं है।

यह मामला विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी द्वारा कथित तौर पर दिए गए ₹डीजे बजाने₹ संबंधी बयान से जुड़ा है। इस बयान को लेकर उनके खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। मामले की जांच राज्य पुलिस का अपराध जांच विभाग कर रहा है। जांच एजेंसी का कहना है कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए अभिषेक बनर्जी की आवाज का नमूना आवश्यक है।

इसी मांग को लेकर अपराध जांच विभाग ने विधाननगर अदालत में आवेदन किया था। अदालत ने 30 जून को अभिषेक बनर्जी की आवाज का नमूना लेने की अनुमति दे दी थी। हालांकि, निर्धारित तिथि पर अभिषेक अदालत में उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने इस आदेश को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

उच्च न्यायालय में दायर याचिका में अभिषेक बनर्जी ने तर्क दिया कि उन्होंने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि संबंधित ऑडियो में आवाज उनकी ही है। ऐसे में जब आवाज की पहचान को लेकर कोई विवाद नहीं है, तो फिर आवाज का नमूना लेने की आवश्यकता नहीं है।

इससे पहले इस मामले में न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की पीठ के समक्ष भी शीघ्र सुनवाई की मांग की गई थी। उस समय न्यायालय ने यह कहते हुए तत्काल हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था कि जांच एजेंसी को किस प्रकार की जांच करनी है और किन साक्ष्यों की आवश्यकता है, यह तय करना अदालत का काम नहीं है। न्यायालय ने कहा था कि मुख्य मामला जिस पीठ के समक्ष लंबित है, उसी के समक्ष अभिषेक अपनी याचिका पर सुनवाई करा सकते हैं।

अब इस मामले में अगली महत्वपूर्ण सुनवाई मंगलवार को संभावित है। वहीं, 8 जुलाई को विधाननगर अदालत ने अभिषेक बनर्जी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत के आदेश के अनुसार, उसी दिन मजिस्ट्रेट और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मौजूदगी में अपराध जांच विभाग द्वारा उनके आवाज के नमूने लिए जाने की प्रक्रिया पूरी की जानी है। ऐसे में मंगलवार को उच्च न्यायालय में होने वाली संभावित सुनवाई इस मामले की आगे की कानूनी दिशा तय करने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

अब सेवाश्रय के झमेले में फंसे अभिषेक बनर्जी

कोलकाता, (नि.सं.)। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर में एक नया मामला दर्ज किया गया है। इस बार उनके द्वारा संचालित ह्यसेवाश्रयह्व स्वास्थ्य शिविरों को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि इन शिविरों में बिना वैध अनुमति के चिकित्सा केंद्र चलाए गए और वहां अवैध रूप से दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों तथा अन्य मशीनों का इस्तेमाल किया गया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, रायनगर निवासी सुकदेव दास की शिकायत के आधार पर डायमंड हार्बर थाने की पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि शिविरों में रेडियोधर्मी पदार्थों का भी अवैध उपयोग किया गया, जिससे आम लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी।

पुलिस ने सांसद अभिषेक बनर्जी सहित अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसे आरोपों में मामला दर्ज किया है। इसके अलावा औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, पीसीपीएनडीटी अधिनियम तथा पश्चिम बंगाल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि अभिषेक बनर्जी और अन्य लोग सुनियोजित आपराधिक साजिश के तहत विभिन्न स्थानों

पर अनधिकृत चिकित्सा केंद्र चला रहे थे, जहां नियमों के विरुद्ध इलाज, दवा वितरण और

सेवा के नाम पर हुआ छल

जांच संबंधी उपकरणों का उपयोग किया गया। इससे जनस्वास्थ्य और सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ।

मामले में आपराधिक साजिश और जनसुरक्षा में बाधा समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। डायमंड हार्बर एसडीपीओ कार्यालय को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस सभी आरोपों की सत्यता की जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में रहने के दौरान अभिषेक बनर्जी ने अपने संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में ह्यसेवाश्रयह्व नाम से मुफ्त स्वास्थ्य शिविर शुरू किए थे। इन शिविरों में दूर-दराज क्षेत्रों के साथ अन्य राज्यों से भी लोग इलाज कराने पहुंचते थे। यह परियोजना काफी लोकप्रिय हुई थी और भविष्य में इसे राज्य के अन्य हिस्सों में भी शुरू करने की योजना की घोषणा की गई थी।

हालांकि विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद अभिषेक बनर्जी लगातार विभिन्न कानूनी मामलों में जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। इसी बीच गुरुवार रात अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि पिछले दो सप्ताह में उनके और उनके कार्यालय से जुड़े करीब 25 लोगों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया है। उनका आरोप है कि कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया और कुछ को घर से उठाकर ले जाया गया ताकि उनके खिलाफ बयान दर्ज कराया जा सके। इसी घटनाक्रम के बीच अब ह्यसेवाश्रयह्व शिविरों में कथित अवैध गतिविधियों को लेकर उनके खिलाफ यह नया मामला दर्ज हुआ है।

प्रथम प्रकाशन 1878
भारतमित्र

संपादकीय

पश्चिम एशिया में संघर्ष की अनिश्चितता के चलते सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था और विनिर्माण ने बढ़ाई चिंता

एचएसबीसी की मासिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, इस वर्ष जून में भारतीय वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय मांग में वृद्धि की रफ्तार 39 महीनों में सबसे कमजोर रही।पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त होने को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के फिर से रफ्तार पकड़ने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर में गिरावट और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ अब देश में विनिर्माण गतिविधियों की वृद्धि भी धीमी पड़ गई है।एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, विनिर्माण में वृद्धि का आंकड़ा इस वर्ष मई के 55.0 से घटकर जून में 54.2 पर पहुंच गया। यही नहीं, नई कारोबारी मांग और अंतरराष्ट्रीय बिक्री की वृद्धि दर सुस्त रहने से वस्तुओं की खरीद, रोजगार सृजन और उत्पादन की रफ्तार भी कम हो गई है। यानी कुछ उपक्रमों को छोड़ दिया जाए, तो देश के ज्यादातर क्षेत्रों की वृद्धि में गिरावट देखी जा रही है, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।हालांकि, महंगाई से राहत दिलाने के लिए तेल कंपनियों ने बुधवार को वाणिज्यिक एलपीजी के 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर पर 183.50 रुपये और विमान ईंधन में पांच रुपये प्रति लीटर की कटौती की है, लेकिन पिछले दिनों बढ़ाए गए दामों के मुकाबले यह राहत बेहद कम है।इसमें दोराय नहीं कि पश्चिम एशिया में संघर्ष से उपजे संकट का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय था, लेकिन सवाल यह है कि सरकार की ओर से इसके प्रभाव को कम करने के लिए समय रहते वैकल्पिक उपाय तलाशने पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? ऐसा भी नहीं है कि सरकार इस संकट की संभावनाओं से अनभिज्ञ थी। दावे किए जाते रहे कि स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, मगर इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम धरातल पर कहीं नजर नहीं आते हैं।एचएसबीसी की मासिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, इस वर्ष जून में भारतीय वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय मांग में वृद्धि की रफ्तार 39 महीनों में सबसे कमजोर रही। इससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि भारतीय निर्यात कारोबार पर कितना गहरा असर पड़ा है। सर्वेक्षण में कई कंपनियों ने माना है कि उन्हें हाल के दिनों में नई नियुक्तियां रोकनी पड़ीं या उन्हें कम कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि लोगों को रोजगार के मोर्चे पर भी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।इसके अलावा मांग और बाजार की स्थिति को लेकर चिंता के कारण जून में निवेशकों और कारोबारियों का भरोसा भी कमजोर पड़ा है। खासकर विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार को लेकर रुख असमंजस भरा रहा है, जिस कारण विदेशी निवेश की निकासी का सिलसिला जारी है।सर्वेक्षण से पता चलता है कि आने वाले दिनों में स्थिति सामान्य होने को लेकर भी भरोसा घट रहा है। यही वजह है कि अगले एक वर्ष में उत्पादन बढ़ने का अनुमान लगाने वाली कंपनियों का अनुपात इस वर्ष मई की तुलना में जून में आधा रह गया है।वहीं, तेल कंपनियों ने पश्चिम एशिया में संघर्ष से कीमतों में आई तेजी के बाद वाणिज्यिक एलपीजी और विमान ईंधन के दामों में पहली बार कटौती की है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में दो वर्ष पहले एक इमारत के भूतल में बारिश का पानी भर जाने से वहां कोचिंग सेंटर में मौजूद तीन युवाओं की मौत हो गई थी। ये वे नौजवान थे, जो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर अपने लिए बेहतर रोजगार की जमीन तलाश रहे थे। यहां भी नियमों का उल्लंघन कर निर्माण हुआ था, मगर संबंधित महकमे के अधिकारियों की मिलीभगत से इसे नजरअंदाज कर दिया गया। इसी तरह का एक मामला हाल में दिल्ली के मालवीय नगर में सामने आया। एक इमारत का अवैध तरीके से विस्तार कर उसे बहुमंजिला होटल बना दिया गया। छह कमरों की विभागीय मंजूरी लेकर 26 कमरे बना दिए गए। इस इमारत में आपात स्थिति के लिए वैकल्पिक निकासी मार्ग और अग्निशमन के पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए थे।

नियमों की अनदेखी कब तक? अवैध निर्माण और लापरवाही बन रहे हैं मौत का कारण

(सुरेश सेठ)

कानून के मुताबिक, रिहायशी भवनों का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। भवन निर्माण से पहले प्रवेश और प्रस्थान के लिए उचित रास्ते बनाए जाने चाहिए। इमारतों में आग लगने या अन्य आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त प्रबंध करना जरूरी है।

चाहे सरकार का निर्देश हो या अदालत का फैसला, कुछ लोग नियमों की अनदेखी कर अपने हित साधने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं, भले ही इससे किसी की जान जोखिम में क्यों न पड़ जाए। सर्वोच्च अदालत ने अपने एक फैसले में कहा कि सरकारी जमीन के अतिक्रमण पर पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिए। सरकार की ओर से भी यह कहा जाता रहा है कि अतिक्रमण करना कानूनी जुर्म है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कानून के मुताबिक, रिहायशी भवनों का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। भवन निर्माण से पहले प्रवेश और प्रस्थान के लिए उचित रास्ते बनाए जाने चाहिए। इमारतों में आग लगने या अन्य आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त प्रबंध करना जरूरी है। मगर इन नियम-कानूनों की कौन परवाह करता है? विकास के नाम पर बहुमंजिला इमारतें या भीड़भाड़ वाले स्थलों पर बेतरतीब निर्माण प्रगति का प्रतीक बनते-बनते मौत का सूचक बनने लगे हैं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में दो वर्ष पहले एक इमारत के भूतल में बारिश का पानी भर जाने से वहां कोचिंग सेंटर में मौजूद तीन युवाओं की मौत हो गई थी। ये वे नौजवान थे, जो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर अपने लिए बेहतर रोजगार की जमीन तलाश रहे थे। यहां भी नियमों का उल्लंघन कर निर्माण हुआ था, मगर संबंधित महकमे के अधिकारियों की मिलीभगत से इसे नजरअंदाज कर दिया गया।

इसी तरह का एक मामला हाल में दिल्ली के मालवीय नगर में सामने आया। एक इमारत का अवैध तरीके से विस्तार कर उसे बहुमंजिला होटल बना दिया गया। छह कमरों की विभागीय मंजूरी लेकर 26 कमरे बना दिए गए। इस इमारत में आपात स्थिति के लिए वैकल्पिक निकासी मार्ग और अग्निशमन के पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए थे। जब आग लगी तो कई लोग इमारत के अंदर ही फंस गए और उनकी मौत हो गई। इनमें से कई लोग ऐसे थे, जो अपने निकट संबंधियों के उपचार के लिए इस होटल में ठहरे हुए थे। इस घटना के बाद विरोध-प्रदर्शन हुए, सरकार की ओर से पीड़ितों के लिए अनुदान राशि घोषित की गई और फिर अवैध निर्माण को गिराकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

इसके बाद नियमों की अनदेखी और विभागीय लापरवाही की दिल दहला देने वाली घटना उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अलीगंज में सामने आई। जिस इमारत को वर्ष 2016 से ढहाने का नोटिस दिया गया था, वहां गैर-कानूनी ढंग से निर्माण किया गया था। इस व्यावसायिक इमारत में कोचिंग सेंटर भी संचालित किया जा रहा था। यहां लगी आग की घटना में विद्यार्थियों सहित पंद्रह लोगों की मौत हो गई। पहली मंजिल पर पक्षी और जानवर रखे गए थे। दूसरी मंजिल पर गोदाम था और तीसरी मंजिल पर कोचिंग सेंटर था। आग गोदाम में लगी और देखते ही देखते पूरी इमारत जल गई। अंदर बैठे छात्र बाहर की ओर भागे, लेकिन निकासी के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं था। बचाव दल ने इमारत की पिछली दीवार तोड़कर कुछ लोगों को बाहर निकाला, तो कुछ छात्र जान बचाने के लिए खिड़की से कूद गए।

इसे शासन-प्रशासन की लापरवाही नहीं तो और क्या कहा जाएगा कि कुछ लोग चंद पैसों के लालच में नियम-कानून का उल्लंघन कर बहुमंजिली इमारतें खड़ी कर देते हैं, जहां आपात स्थिति के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किए जाते। ऐसी इमारतों को कहीं होटल में तब्दील कर दिया जाता है, तो कहीं कोचिंग सेंटर संचालित किए जाते हैं। जाहिर है कि यह विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। अदालतों की ओर से ऐसे मामलों में कई बार निर्देश और चेतावनियां दी जा चुकी हैं, लेकिन इन्हें अमल में लाने का जिन पर जिम्मा है, वे आंखें मूंदे बैठे हैं। प्रशासन में छिपी काली भेड़ें नियमों का उल्लंघन करने वालों का रास्ता साफ कर देती हैं। लखनऊ के अलीगंज में जिस व्यावसायिक इमारत में आग लगी थी, वह वर्ष 2014 में बनाई गई थी। हैरत की बात है कि नियमों की अनदेखी करने पर निर्माण के दो साल बाद ही इस इमारत को गिराने का नोटिस दे दिया गया था, इसके बावजूद इसका व्यावसायिक इस्तेमाल होता रहा। अब जब आग की घटना में पंद्रह लोगों की जान चली गई, तब जाकर स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। सरकार ने इस घटना की जांच के लिए विशेष दल गठित किया और कानपुर में ऐसे ही 22 और कोचिंग संस्थान सील कर दिए गए। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नियमों की अनदेखी और अवैध तरीके से निर्माण कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। अलीगंज के मामले में भवन मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और लापरवाही बरतने के आरोप में चार विभागीय अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। कुल मिलाकर सोलह कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। पीड़ित परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई। मगर सवाल है कि बार-बार होने वाली इस तरह की घटनाओं के बाद कार्रवाई क्या सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने जैसी नहीं है? ऐसी क्या वजह है कि अवैध तरीके से भवन निर्माण और नियमों की अनदेखी करने वालों को शुरू में नहीं रोका जा सकता? ऐसे लोगों के भीतर कानून का खौफ क्यों नहीं है और क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि वे जो कर रहे हैं, उसे कोई नहीं देख रहा? सवाल है कि देश में 'यह सब चलता है' की मनोवृत्ति कब खत्म होगी? नौकरशाही को जब सुविधा केंद्रों में बदला जाता है, तो वे असुविधा केंद्र कैसे बन जाते हैं? जो जनप्रतिनिधि चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की बात करते हैं, जब कभी उनकी तिजोरियों को खंगाला जाता है, तो बेहिसाब संपत्ति का पता चलता है। इससे साफ है कि व्यवस्था में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है, जिसकी आग में आम आदमी झुलस रहा है। अगर प्रशासनिक ढांचा ईमानदार हो और कानून तोड़ने वालों को तुरंत दंडित किया जाए, तो कई समस्याएं शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। मगर ऐसा केवल चुनावी घोषणाओं में ही होता है और उसके बाद दिल्ली के राजेंद्र नगर, मालवीय नगर तथा उत्तर प्रदेश के अलीगंज अग्निकांड जैसी घटनाओं का सिलसिला जारी रहता है। आखिर सरकार और समाज कब जागेंगे कि नियम-कानूनों का उल्लंघन करके हथेलियों पर धन-दौलत की फसल उगाने वालों पर शिकंजा कसा जाए और आम लोगों को भी सम्मान से जीने और अपने सपने पूरे करने का अवसर मिल सके। यह याद रखना चाहिए कि जब तक प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक सुधार नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार और कानून का उल्लंघन कर आमजन की जान को जोखिम में डालने का कुत्सित प्रयास भी अनवरत जारी रहेगा।

दिल्ली मेट्रो का यह फैसला- बढ़ जाएगी यात्रियों की परेशानी

(संतोष कुमार पाठक)

लोगों ने रियायती दरों पर पास जारी नहीं करने और दिल्ली मेट्रो के महंगे किराए को भी इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें लगा कि अब देश की राजधानी में उन्हें विश्वस्तरीय परिवहन व्यवस्था मिलेगी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली मेट्रो एक के बाद एक ऐसा फैसला कर रहा है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है।

दुनिया भर के विकसित देशों के विकास की कहानी को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें दो चीजें आपको कॉमन नजर आएंगी। बेहतर सड़क और शानदार सार्वजनिक परिवहन (बस, मेट्रो, ट्रेन आदि) व्यवस्था। कई मायनों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर सरकार द्वारा किए गए खर्च को बड़ा निवेश ही माना जाता है क्योंकि दशकों तक इसका फायदा उस देश की अर्थव्यवस्था को मिलता रहता है।

भारत जैसे देश के लिए बेहतर, सुगम और तेज रफ्तार वाली सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था तो और भी जरूरी है क्योंकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल और गैस के आयात पर ही खर्च होता है। तमाम दावों के बीच कड़वी सच्चाई तो यही है कि भारत पेट्रोल-डीजल और गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है और हमारी निर्भरता किस हद तक है, इसका अंदाजा ईरान बनाम अमेरिका की लड़ाई के असर के रूप में हम सबको दिख ही गया है।

भारत के लगभग हर शहर में सड़कों का निर्माण तेजी से हो रहा है लेकिन सार्वजनिक परिवहन की लचर व्यवस्था के कारण लोग उससे भी ज्यादा तेजी से पर्सनल गाड़ियां खरीदते हैं और नतीजा हर तरफ ट्रैफिक जाम यानी पेट्रोल-डीजल और गैस की बर्बादी।

दिल्ली में भी मेट्रो का तेजी से विस्तार तो हो रहा है लेकिन यह दिल्ली की जरूरतों के लिहाज से अभी भी काफी पीछे है। एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को नकारते हुए दिल्ली मेट्रो में इसकी शुरुआत के समय ही यह फैसला किया गया था कि स्टूडेंट्स, बुजुर्ग और पत्रकार सहित किसी भी कैटेगरी में किसी को भी रियायती दरों पर कोई पास जारी नहीं किया जाएगा। थोड़े बहुत विरोध के बाद सबने इसे स्वीकार कर लिया जबकि दिल्ली की सरकारी परिवहन व्यवस्था यानी डीटीसी बसों में कई कैटेगरी के यात्रियों को रियायती दरों पर पास आज भी जारी किए जाते हैं।

लोगों ने रियायती दरों पर पास जारी नहीं करने और दिल्ली मेट्रो के महंगे किराए को भी इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें लगा कि अब देश की राजधानी में उन्हें विश्वस्तरीय परिवहन व्यवस्था मिलेगी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली मेट्रो एक के बाद एक ऐसा फैसला कर रहा है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारी शायद यह भूल गए हैं कि उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी उन यात्रियों के प्रति है जो उन्हें महंगा किराया देकर मेट्रो में सफर करते हैं। ये अधिकारी, यह भी भूल जाते हैं कि ये भारत है, जहां नैतिकता से जुड़े मुद्दों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है।

दिल्ली मेट्रो ने अब यह फैसला किया है कि वो यात्रियों को अब विज्ञापन सिर्फ दिखाएगा ही नहीं बल्कि सुनाएगा भी। यानी जब आप मेट्रो के अंदर सफर करते समय, यह सुनने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है ताकि आप अपने स्टेशन पर उतरने की तैयारी कर सकें तो इस बीच आपको दिल्ली मेट्रो अलग-अलग कंपनियों के विज्ञापन सुनने को मजबूर कर देगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी ने अपने नॉन-ऑपरेशन रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ट्रेन के अंदर ऑडियो विज्ञापन शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि अधिकारियों ने यह दावा भी किया है कि कंपनियों के ऑडियो विज्ञापन से मेट्रो के अंदर होने वाली जरूरी घोषणाओं जैसे- अगला स्टेशन कौन सा है, दरवाजे बंद होने वाले हैं, दरवाजों से हटकर खड़े रहें, यह ट्रेन कहां तक जाएगी पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं, आप खुद ही सोचिए।

आपको बता दें कि, वर्तमान में भी दिल्ली मेट्रो की कमाई का सबसे बड़ा जरिया मेट्रो ऑपरेशन यानी इसपर सफर करने वाले यात्रियों से ही आता है। जबकि अन्य कामों यानी गैर ऑपरेशनल गतिविधियों से कुल कमाई का सिर्फ 20 प्रतिशत हिस्सा ही आता है जिसमें हर तरह के विज्ञापन (स्टेशनों के नाम तक बेचना शामिल है) शामिल हैं। इसके अलावा मेट्रो स्टेशनों पर दुकानों, कियोस्क, एटीएम और पार्किंग से भी कमाई होती है।

जब यात्री खचाखच भरे मेट्रो में (अगला स्टेशन जानने के लिए) डिस्प्ले बोर्ड तक नहीं देख पाता है, तब मेट्रो हमें विज्ञापन सुनाना चाहता है। लेकिन यह शायद पहला मामला नहीं है जब दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने ऐसा फैसला किया हो। यात्रियों की मुश्किलें बढ़ाने वाले फैसलों की तो एक लंबी लिस्ट बनाई जा सकती है। यात्रियों की सुविधा के लिए एक सिंपल सा स्मार्ट कार्ड जारी किया गया था, जिसे यात्री बड़ी ही आसानी से किसी भी स्टेशन से बनवा सकता था और खराब होने पर लौटा भी सकता था। अब मेट्रो ने बैंक से जुड़े कार्ड को थोपने के लिए साधारण वाला स्मार्ट कार्ड छापना ही बंद कर दिया है। प्लास्टिक वाला पुराना टोकन बंद करके, कागज वाला देने लगे हैं जिससे हर स्टेशन के कस्टमर केयर पर आपको कागजों का ढ़ेर नजर आएगा। मेट्रो ने नहीं ले जाने वाले सामानों की लंबी-चौड़ी लिस्ट जारी कर रखी है लेकिन उन्हें स्टेशनों पर चलाए जा रहे रेस्टोरेंट में कोई खतरा नज़र नहीं आता। हद तो तब हो जाती है जब ये अपने स्टेशनों पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाकर कंडोम का भी विज्ञापन करते नज़र आते हैं। अब ये वक्त आ गया है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को यह बताया जाए कि इसके गठन का मूल उद्देश्य पूरी दिल्ली को जोड़ना था एवं है(अब तो इसमें एनसीआर का इलाका भी शामिल हो गया है) और यात्रियों को तेज और सुगम सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था देना है।

पारिवारिक और सामाजिक पुनर्वास की मानवीय पहल

(उमेश चतुर्वेदी)

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2700 नक्सली आत्म समर्पण कर चुके है। इन पूर्व नक्सलियों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय सहयोग के साथ नक्सल प्रभावित राज्यों की सरकारें कई सारी योजनाएं चला रही हैं। नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित रहे छत्तीसगढ़ और झारखंड में आर्थिक सहयोग, रोजगार, घर आदि की सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे नक्सलियों के पुनर्वास को गति मिली है। लेकिन पूर्व नक्सलियों के पुनर्वास कार्यक्रमों में एक अनूठी मुहिम चलाई जा रही है। यह विशेष मुहिम सिर्फ छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ही चला रही है। इस मुहिम को पारिवारिक और सामाजिक पुनर्वासन कहा जा सकता है।

देश के एक तिहाई जिलों पर लाल आतंक के रूप में कुख्यात रहा नक्सलवाद अब आखिरी सांसें गिन रहा है। गृहमंत्री अमित शाह के दावे के मुताबिक, 31 मार्च 2026 तक देश तकरीबन नक्सलमुक्त हो चुका है। इस दौरान सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में ज्यादातर बड़े नक्सली कमांडर मारे जा चुके हैं, या कई ने आत्मसमर्पण कर दिया है।

अभी हाल ही में पिता दिवस गुजरा है। इस दिन सोशल मीडिया समेत तमाम जगहों पर हुई चर्चाओं में एक बात प्रमुखता से छायी रही। ऐसा कहा गया कि पिता बनने के बाद लोगों की शख्सियत में बदलाव आ जाता है। चूंकि जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लिहाजा इन दायित्वों के चलते कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी नरम हो जाता है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने जब पूर्व नक्सलियों की जबरिया कराई गई नसबंदी को खोलने वाले जटिल ऑपरेशन को हरी झंडी दिखाई, पता नहीं, उसके दिमाग में यह तथ्य था या नहीं। लेकिन उसकी इस कोशिश से कभी इंन्सानी खून से लाल रही बस्तर की धरती के कई आंगन किलकारियां गूंज रही हैं। देश के एक तिहाई जिलों पर लाल आतंक के रूप में कुख्यात रहा नक्सलवाद अब आखिरी सांसें गिन रहा है। गृहमंत्री अमित शाह के दावे के मुताबिक, 31 मार्च 2026 तक देश तकरीबन नक्सलमुक्त हो चुका है। इस दौरान सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में ज्यादातर बड़े नक्सली कमांडर मारे जा चुके हैं, या कई ने आत्मसमर्पण कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2700 नक्सली आत्म समर्पण कर चुके है। इन पूर्व नक्सलियों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय सहयोग के साथ नक्सल प्रभावित राज्यों की सरकारें कई सारी योजनाएं चला रही हैं। नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित रहे छत्तीसगढ़ और झारखंड में आर्थिक सहयोग, रोजगार, घर आदि की सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे नक्सलियों के पुनर्वास को गति मिली है। लेकिन पूर्व नक्सलियों के पुनर्वास कार्यक्रमों में एक अनूठी मुहिम चलाई जा रही है। यह विशेष मुहिम सिर्फ छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ही चला रही है। इस मुहिम को पारिवारिक और सामाजिक पुनर्वासन कहा जा सकता है।

दरअसल नक्सली संगठनों में फील्ड कार्य कर रहे नक्सलियों के लिए अमानवीय प्रथा थी। फील्ड में काम कर रहे कम उम्र के नक्सलियों की अमानवीय तरीके से जबरिया नसबंदी करा दी जाती थी, ताकि नक्सली कार्य करते वक्त वे अपना परिवार न बढ़ा सकें। नक्सली संगठनों में महिला नक्सली भी सक्रिय थीं, उनके बीच रिश्ते पनपने संभव थे। लेकिन उन रिश्तों से बच्चे ना हों, इसलिए पुरूष नक्सलियों को जबरदस्ती नसबंदी के लिए मजबूर किया गया। जिनमें बहुत सारे नक्सलियों की उम्र बेहद कम थी। लेकिन सरकारी मुहिम के बाद जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया तो उनके मन में भी परिवार बसाने और अपने घर-आंगन में किलकारी गूंजने की चाहत जगी। चूंकि इनकी नसबंदी हो चुकी थी, लिहाजा इन्हें मन-मसोस कर रह जाना पड़ता था। छत्तीसगढ़ सरकार इन्हीं समर्पित प्रजनन उम्र वाले नक्सलियों के लिए पारिवारिक तौर पर ज्यादा सक्रिय होने के लिए यह मानवीय पहल शुरू की है।

पशुपति यानी नेपाल से लेकर तिरूपति यानी आंध्र के जंगली गलियारे तक तूती बोलने के दौर में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित था। खूंखार नक्सलियों के लिए कुख्यात इसी बस्तर संभाग से छत्तीसगढ़ सरकार ने मानवीय पहल शुरू की है। इसके तहत प्रजनन की उम्र वाले उन नक्सलियों का रिवर्स वैसेक्टॉमी शुरू किया है। नसबंदी करा चुके लोगों के लिए रिवर्स वासेक्टॉमी एक तरह से उनकी नसों को फिर से खोलने और उन्हें प्रजनन योग्य बनाने की जटिल प्रक्रिया है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने इस अनूठी पहल को यूरोलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों की मदद से शुरू किया है। 14 जून तक के आंकड़ों के अनुसार, दो चरणों में 73 पूर्व नक्सलियों की नसबंदी खोलने का ऑपरेशन पूरा किया जा चुका है। पहले चरण में 33 पूर्व नक्सलियों को खुशहाल जिंदगी गुजारने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया तो दूसरे चरण में 40 पूर्व नक्सलियों की नसबंदी को खोला गया। पहले चरण में जिन 33 पूर्व नक्सलियों की नसबंदी खोलने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, उनमें से 27 के आंगन किलकारियों से गूंज रहे हैं। बस्तर के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के अनुसार, बस्तर के एक पूर्व नक्सली के घर दो महीने पहले ही बच्ची का जन्म हो चुका है। उस पूर्व नक्सली का परिवार इस बच्ची के साथ अपना पारिवारिक जीवन आनंद से बिता रहा है।

आमतौर नसबंदी खोलने के इस जटिल ऑपरेशन के लिए बड़े शहरों और महानगरों के सुविधा संपन्न अस्पतालों में जाना पड़ता है। लेकिन यह पहला मौका है, जब छत्तीसगढ़ के दूर-दराज के बस्तर संभाग में स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर इस जटिल ऑपरेशन प्रक्रिया को सफलता के साथ अंजाम तक पहुंचाया गया। इस पहल में बस्तर के जिला प्रशासन के साथ ही बस्तर पुलिस और यूरोलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया के पश्चिमी जोन की बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका रही। यूरोलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और इंदौर निवासी डॉक्टर राजेश कुकरेजा का कहना है कि बस्तर जैसे इलाके में इतने बड़े स्तर पर नसबंदी खोलने का सफल ऑपरेशन किया जाना चिकित्सा क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि है। इस ऑपरेशन की शुरूआत जगदलपुर के महारानी अस्पताल में की गई। इसके लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए। जगदलपुर के जिला अस्पताल में नसबंदी खोलने के विशेष शिविरों में देश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुशील राठी, डॉ. ललित शाह एवं डॉ. योगेश बरापात्रे सहित इंदौर के डॉ. राजेश कुकरेजा, पुणे के डॉ. सागर भालेराव और डॉ. राहुल, महाराष्ट्र के नांदेड़ के डॉ. अभिषेक, मुंबई के डॉ. निनाद तंबोली और डॉ. पार्थ मानेक के साथ ही रायपुर के डॉ. राहुल कपूर एवं डॉ. घनश्याम हटवार की टीम ने पूर्व नक्सिलियों का सफल ऑपरेशन किया है। इनके सहयोग के लिए छह स्थानीय डॉक्टरों सहित करीब 50 सदस्यों वाली मेडिकल टीम जुटी रही। इतिहास

छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल बाकी राज्यों द्वारा नक्सलियों के आर्थिक और जमीनी पुनर्वास नीति से अलग है। विष्णुदेव साय सरकार की इस मानवीय पहल की प्रशंसा मेडिकल जगत के साथ ही समाजविज्ञानी भी कर रहे हैं। इस पहल के तहत शारीरिक और मेडिकल जांच के साथ ही प्रजनन योग्य पाए जाने वाले नक्सलियों के ही ऑपरेशन किए जाते हैं। इनमें चालीस साल तक की उम्र वाले पूर्व नक्सलियों को ही प्राथमिकता दी जाती है। जगदलपुर के महारानी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय प्रसाद के मुताबिक, राज्य सरकार की पहल पर जल्द ही तीसरे चरण का भी शिविर लगाने की तैयारी है, जिसमें दो दर्जन से ज्यादा पूर्व नक्सलियों के ऑपरेशन किये जायेंगे। छत्तीसगढ़ की यह मानवीय पहल समर्पित नक्सलियों को ना सिर्फ अपने समाज, बल्कि परिवार से भी जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह पहल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा रणनीति से आगे बढ़कर विश्वास निर्माण और सामाजिक-मानवीय पुनर्वास मॉडल के रूप में आगे आ रहा है। ये 73 ऑपरेशन महज चिकित्सकीय आंकड़ा नहीं है, बल्कि इन परिवारों की उम्मीद और सामान्य जीवन की ओर आगे बढ़ने का भी प्रतीक है। उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड और दूसरे नक्सल प्रभावित राज्यों की सरकारें भी इस पहल से प्रेरित होंगी। लेखक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक हैं..। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

विपक्षी को भी मिलेगा समानता का लोकतांत्रिक अधिकार: शुभेंदु अधिकारी

कोलकाता, (नि.सं.)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित दो दिवसीय ऑरिएंटेशन (अभिमुखीकरण) कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान विपक्षी विधायकों को अधिक लोकतांत्रिक अधिकार और सम्मान देने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान विपक्ष के लिए पर्याप्त लोकतांत्रिक स्थान नहीं था, लेकिन उनकी सरकार इस व्यवस्था को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1977 से 2011 तक चले वाम मोर्चा शासन के दौरान अधिकांश निर्णय सत्तारूढ़ दल के कार्यालय से संचालित होते थे। वहीं 2011 से 2026 तक के शासनकाल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उस अवधि में विपक्षी विधायकों को उचित सम्मान नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी विधायकों के टेलीफोन तक प्रखंड विकास अधिकारी और थाना प्रभारी नहीं उठाते थे तथा सरकारी कार्यक्रमों में केवल सत्तारूढ़ दल के विधायकों को आमंत्रित किया जाता था।

उन्होंने कहा कि वह स्वयं पांच वर्ष तक विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे, लेकिन उन्हें एक भी सरकारी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी सरकार के पहले दो महीनों में उन्होंने इस व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग डेढ़ महीने में आयोजित पांच प्रशासनिक बैठकों में सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों के विधायकों को आमंत्रित किया गया। साथ ही विपक्ष को बजट प्रक्रिया में भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य का विकास सभी दलों को साथ लेकर ही संभव है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस, दोनों की पूर्ववर्ती सरकारों की विधानसभा की कार्यप्रणाली को लेकर भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अब भी विधानसभा में मतदान कागज के माध्यम से होता है और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली लागू नहीं की गई है। विधानसभा के बुनियादी ढांचे का भी आधुनिकीकरण आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों के विधायकों की भूमिका और जनसंपर्क को मजबूत करना जरूरी है। सरकार का उद्देश्य दल नहीं, बल्कि जनता के लिए काम करना है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सभी के सहयोग से पश्चिम बंगाल एक बार फिर देश का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

चार सप्ताह में यूसीसी बिल पर गठित समिति देगी रिपोर्ट

अगस्त में विधानसभा में होगा पेश

कोलकाता, (नि.सं.)। पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पश्चिम बंगाल समान नागरिक संहिता, 2026 के मसौदा विधेयक को मंजूरी दी गई। अब इस मसौदे को परीक्षण और सुझावों के लिए उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति के पास भेजा जाएगा।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, समिति अगले चार सप्ताह के भीतर मसौदा विधेयक का परीक्षण कर अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपेगी। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार अंतिम विधेयक तैयार करेगी और इसे अगस्त में होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 29 जून को विधानसभा में इस प्रस्तावित कानून को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि राज्य के आदिवासी, मूल निवासी, कुर्मी तथा अन्य मान्यता प्राप्त प्राचीन जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा था कि यह निर्णय उत्तराखंड और गुजरात में अपनाए गए मॉडल के अनुरूप लिया गया है, जहां जनजातीय समुदायों को विशेष छूट प्रदान की गई है।

प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का उद्देश्य राज्य में धर्म आधारित अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर विवाह, तलाक, भरण-पोषण, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े नागरिक मामलों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। सरकार का कहना है कि इससे सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित होगी तथा विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के कारण उत्पन्न होने वाली असमानताओं को समाप्त किया जा सकेगा।

यदि यह विधेयक विधानसभा से पारित होकर कानून का रूप लेता है, तो पश्चिम बंगाल समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन जाएगा। इससे पहले गुजरात, उत्तराखंड और असम में समान नागरिक संहिता लागू की जा चुकी है।

गुरुवार रात तक हुई मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को सरकारी खर्चों में सख्त नियंत्रण रखने और अनावश्यक व्यय पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं में अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें तुरंत बाहर किया जाए, ताकि सरकारी संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके और योजनाओं के संचालन में वित्तीय बोझ कम किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी विभागों को राजस्व रिसाव रोकने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। विशेष रूप से पत्थर खदानों और बालू खनन जैसे क्षेत्रों में कर संग्रह से जुड़े राजस्व की निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया गया। सरकार का मानना है कि पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान इन क्षेत्रों में व्यापक भ्रष्टाचार के कारण राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ था।

बैठक में मंत्रिमंडल ने सीमा सुरक्षा से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इसके तहत विभिन्न जिलों में सरकारी स्वामित्व वाली भूमि को सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। इस भूमि का उपयोग सीमा चौकियों के निर्माण, सीमा पर बाड़ लगाने तथा सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण सहित अन्य सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

इसके अलावा राज्य में न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से 9 जिलों में 9 नए त्वरित न्यायालय स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इन न्यायालयों के संचालन के लिए 35 नए पदों के सृजन को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की। राज्य सरकार का कहना है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू करना है, जबकि अनुसूचित जनजातियों और पारंपरिक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों तथा उनकी परंपराओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। अगस्त में विधानसभा में विधेयक पेश होने के बाद इस पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है।

कूचबिहार में मां आहार कैंटीन की शुरूआत

कूचबिहार, (नि.सं.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चुनावी वादे को पूरा करते हुए जिले में ह्यमां आहारह्ल कैंटीन की शुरूआत कर दी है। शुक्रवार से इस कैंटीन में मात्र पांच रुपये में आम लोगों को मछली-भात परोसा जा रहा है। पहले एमजेएन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में कूचबिहार नगरपालिका की देखरेख में ह्यमां कैंटीनह्ल से पांच रुपये में अंडा-भात मिलता था, जिसे अब नया नाम देकर ह्यमां आहारह्ल कर दिया गया है।

उद्घाटन के दिन कैंटीन के मेन्यू में भात और मछली का झोल शामिल था, जिसका लाभ करीब तीन सौ लोगों ने उठाया।

मात्र पांच रुपये में मछली-भात मिलने से मरीजों और उनके परिजनों में खुशी देखी गई। प्रशासन के अनुसार, यह सेवा अब नियमित रूप से उपलब्ध रहेगी। अंडा-भात के साथ अब सप्ताह में दो दिन मछली भी मेन्यू में शामिल की जाएगी।

यह कैंटीन प्रतिदिन दोपहर एक बजे से तीन बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी, जहां सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की इस जनकल्याणकारी पहल से शहर के लोगों में संतोष और उत्साह देखा जा रहा है।

डीआरएम ने किया बरकाकाना स्टेशन एवं बरवाडीह केंद्रीय विद्यालय का निरीक्षण

धनबाद। आज मंडल रेल प्रबंधक अखिलेश मिश्र द्वारा बरकाकाना स्टेशन का विस्तृत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर, पार्किंग क्षेत्र, कोचिंग लाइन तथा कंट्रोल कार्यालय का जायजा लेते हुए यात्री सुविधाओं, परिचालन व्यवस्था, स्वच्छता, रखरखाव कार्यों एवं उपलब्ध आधारभूत संसाधनों की गहन समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा एवं संरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने, यात्री सुविधाओं में निरंतर सुधार लाने तथा परिचालन दक्षता एवं कार्यकुशलता को और सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इसके उपरांत मंडल रेल प्रबंधक द्वारा बरवाडीह स्थित केंद्रीय विद्यालय परिसर का निरीक्षण किया गया। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने तथा परिसर की सुरक्षा एवं स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया।

अन्नपूर्णा योजना के पैसे न मिलने पर गुस्साए लोगों ने नगरपालिका में किया प्रदर्शन

चेयरमैन पर फेंके अंडे

कूचबिहार, (नि.सं.)। अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत खाते में पैसे नहीं आने से नाराज लोगों ने शुक्रवार को जिले के मेखलीगंज नगरपालिका में जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों के विरोध का सामना खुद नगरपालिका के चेयरमैन प्रभात पाटनी को करना पड़ा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि प्रदर्शनकारियों ने उनके ऊपर अंडे फेंके।जानकारी के अनुसार, शहर के एक हिस्से की महिलाएं अन्नपूर्णा योजना की राशि नहीं मिलने की शिकायत लेकर नगरपालिका पहुंची। वे सीधे चेयरमैन के कक्ष में घुसकर उनसे बातचीत करने लगी। आरोप है कि इसी दौरान भीड़ अचानक उग्र हो गई और चेयरमैन पर अंडे फेंकने लगी। हालात ऐसे हो गए कि उन्हें कमरे से बाहर निकलने में भी मुश्किल हुई और प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया।

स्थिति बिगड़ते देख मेखलीगंज थाने के ओसी मोहम्मद शाहबाज के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को काबू में किया। बाद में भाजपा नेता आशेकर रहमान भी मौके पर पहुंचे और लोगों व चेयरमैन से बातचीत किया।प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने योजना के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक उनके खातों में पैसा नहीं आया है।

शहीद दिवस रैली में सड़क अवरोध के आरोप पर ममता और अभिषेक बनर्जी से हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

कोलकाता, (नि.सं.)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को अवमानना याचिका पर 4 सप्ताह के भीतर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2025 में आयोजित तृणमूल कांग्रेस की 21 जुलाई को शहीद दिवस रैली के दौरान अदालत के पूर्व आदेश का उल्लंघन करते हुए प्रमुख सड़कों को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा राय की खंडपीठ ने दोनों नेताओं को आरोपों पर अपना पक्ष शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को उनके जवाब पर दो सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।

याचिका में कहा गया है कि मई 2018 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निर्देश दिया था कि सार्वजनिक सभा या रैली के दौरान किसी भी प्रमुख सड़क को पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया था कि पैदल यात्रियों और आपातकालीन सेवाओं के वाहनों के आवागमन के लिए रास्ता हर हाल में खुला रखा जाना चाहिए। अधिवक्ता श्रीकांत दत्त ने 19 जून को अवमानना याचिका दायर कर दावा किया कि 21 जुलाई, 2025 को आयोजित तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली के दौरान कोलकाता के एस्प्लेनेड क्षेत्र में प्रमुख सड़कों को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया, जिससे उच्च न्यायालय के 2018 के आदेश का उल्लंघन हुआ।

इससे पहले खंडपीठ ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अब अदालत ने दोनों नेताओं को 4 सप्ताह के भीतर शपथपत्र दाखिल करने का आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त निर्धारित की है।

राशन में गड़बड़ी के आरोप में ग्राहकों ने दुकान में जड़ा ताला

कूचबिहार, (नि.सं.)। राशन सामग्री कम तौलने के आरोप को लेकर शुक्रवार दोपहर जिले के फालाकाटा के बंशिधरपुर गांव में भारी तनाव की स्थिति पैदा हो गई। फालाकाटा दो ग्राम पंचायत क्षेत्र के एक राशन दुकान के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें थी, आज खुलकर सामने आने पर स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे। जानकारी के अनुसार, राशन लेने पहुंचे ग्राहकों ने देखा कि चावल और गेहूं के वजन में भारी गड़बड़ी है। एक ग्राहक ने 21 किलो गेहूं लेने के बाद बाहर तौल कर देखा तो वह मात्र 18 किलो निकला। वहीं 14 किलो चावल की जगह सिर्फ 12 किलो ही दिया गया। इसी तरह लगभग सभी ग्राहकों के साथ कम तौलने की बात सामने आई। इसके बाद नाराज ग्राहकों ने बाहर से वजन मशीन लाकर दुकान की मशीन से मिलान किया, जिसमें बड़ा अंतर पाया गया। घटना से गुस्साए लोगों ने राशन दुकान के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और दुकान में ताला लगा दिया। सूचना पाकर फालाकाटा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में भी वजन में अंतर साफ दिखाई दिया। इस मामले में दुकान के दो कर्मचारियों अभिजीत सरकार और निताई विश्वास को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने ले गई।

भू-माफिया के सरकारी जमीन पर चार मंजिला होटल बनाने की शिकायत

धनबाद प्रतिनिधि । उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने आज जनता दरबार का आयोजन कर कतरास, चिरकुंडा, निरसा, बाघमारा, तोपचांची, धनबाद, झरिया, कलियासोल सहित जिले के विभिन्न क्षेत्र से आए आम जनों की शिकायत सुनी। जनता दरबार में हाउसिंग कॉलोनी से आए व्यक्ति ने उपायुक्त को बताया कि वहीं का एक यूट्यूबर, जो अपने को मीडिया कर्मी भी बताता है, धौंस जमा कर कॉलोनी के सार्वजनिक नाले का अतिक्रमण कर उसपर अवैध निर्माण कर रहा है। शिकायतकर्ता ने साक्ष्य के रूप में कई फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किए। मामले पर त्वरित संज्ञान लेकर उपायुक्त ने हाउसिंग बोर्ड को तत्काल इसकी जांच करके कारवाई करने का निर्देश दिया।

वहीं हीरापुर से आई एक महिला ने उपायुक्त को बताया कि भू-माफिया द्वारा षड्यंत्र कर उन्हें उनके एकमात्र निवास स्थान से बेदखल कर जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। महिला ने बताया कि भू-माफिया द्वारा नगर निगम को गलत जानकारी देकर और दिग्भ्रमित कर उसके मकान को जबरन तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि उक्त भू-माफिया ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से एक चार मंजिला होटल का निर्माण कर लिया है। मामले पर संज्ञान लेकर उपायुक्त ने अनुमंडल दंडाधिकारी को इसकी जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

राजनीति से अछूती रही है देशप्रिय पार्क की दुर्गा पूजा

कोलकाता, (नि.सं.)। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद दुर्गा पूजा समितियों को लेकर विभिन्न तरह की चचाओं और दावों का दौर जारी है। इसी बीच दक्षिण कोलकाता की ऐतिहासिक देशप्रिय पार्क दुर्गोत्सव समिति को लेकर भी कई तरह की

दशकों से होता आ रहा भव्य आयोजन

अटकलें सामने आई हैं। हालांकि, समिति के इतिहास और उसके संचालन की परंपरा पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि देशप्रिय पार्क दुर्गोत्सव समिति का किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक नेता के प्रत्यक्ष नेतृत्व से कभी संबंध नहीं रहा है।

साल 1938 में स्थापित यह पूजा समिति दक्षिण कोलकाता की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित सार्वजनिक दुर्गा पूजा समितियों में गिनी जाती है। पिछले लगभग 90 वर्षों से समिति का संचालन स्थानीय नागरिकों, क्लब सदस्यों और आयोजकों की भागीदारी से होता आया है। समिति की पहचान हमेशा अपनी भव्य कलात्मक प्रस्तुतियों, सामाजिक गतिविधियों और सांस्कृतिक विरासत के कारण बनी रही है, न कि किसी राजनीतिक संरक्षण के कारण।

हाल के दिनों में यह दावा किया जा रहा है कि कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर परिषद सदस्य देबाशीष कुमार का समिति पर प्रभाव या नियंत्रण था। हालांकि पूजा समिति के करीब चार दशक पुराने सदस्य दीपंकर सेन के अनुसार देवाशीष कुमार देशोप्रिया पार्क क्षेत्र के स्थानीय पार्षद होने के कारण पूजा के दौरान अन्य जनप्रतिनिधियों की तरह कार्यक्रमों में आते-जाते रहे,

लेकिन समिति में उन्होंने कभी अध्यक्ष, सचिव, कार्यकारी अध्यक्ष या किसी अन्य महत्वपूर्ण संगठनात्मक पद की जिम्मेदारी नहीं संभाली। समिति का प्रशासनिक संचालन स्वतंत्र रूप से उसके पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा किया जाता रहा है। सेन ने बताया कि देशोप्रिया पार्क दुर्गोत्सव समिति को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान वर्ष 2015 में मिली, जब यहां 88 फीट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई। इसके बाद हजार भुजाओं वाली दुर्गा प्रतिमा, माहिष्मती महल तथा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्थापत्य शैलियों पर आधारित विषयों ने इस पूजा को वैश्विक पहचान दिलाई।

समिति की पहचान हमेशा उसकी कलात्मक उत्कृष्टता और नवाचार से जुड़ी रही है।

समिति कै एक और वरिष्ठ सदस्य गौतम मैत्रा ने हिन्दुस्थान समाचार से विशेष बातचीत में कहा, ₹समिति वर्ष भर रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच, राहत कार्य, खेलकूद प्रतियोगिताएं तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता जैसे सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित करती रही है। यही कारण है कि देशोप्रिया पार्क दुर्गोत्सव समिति को केवल एक पूजा आयोजन नहीं, बल्कि दक्षिण कोलकाता की सामाजिक-सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखा जाता है।₹

कोलकाता की कई प्रमुख दुर्गा पूजा समितियां समय-समय पर विभिन्न राजनीतिक नेताओं या जनप्रतिनिधियों से जुड़ी रही हैं। इनमें चेतला अग्रणी, सुरुचि संघ, उदयन संघ, श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब, त्रिधारा सम्मिलनी, एकडालिया एवरग्रीन, हिंदुस्तान पार्क और भवानीपुर 75 पल्ली जैसी समितियों के साथ अलग-अलग राजनीतिक हस्तियों की सक्रिय भूमिका चर्चा का विषय रही है। इसके विपरीत, देशप्रिय पार्क दुर्गोत्सव समिति ने अपनी स्थापना से अब तक स्वयं को राजनीतिक नेतृत्व से अलग रखते हुए स्वतंत्र सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था के रूप में अपनी पहचान बनाए रखी है।

समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि देशप्रिय पार्क दुर्गा पूजा की सबसे बड़ी खासियत उसकी गैर-राजनीतिक परंपरा, स्थानीय लोगों की भागीदारी और सांस्कृतिक विरासत रही है। यही वजह है कि बदलते राजनीतिक परिवेश के बावजूद इस पूजा की मूल पहचान आज भी उसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत से ही जुड़ी हुई है।

पूर्व रेलवे

निविदा सूचना सं.: ईएलएस/एचडब्ल्यूएच/10/563/ईएमयू (खुली निविदा) दो पैकेट प्रणाली के सेवा अनुबंध में ई-निविदा प्रणाली हेतु, दिनांक: 30.06.2026, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (ईएमयू), पूर्व रेलवे, हावड़ा मंडल, नई डीआरएम बिल्डिंग, चतुर्थ तल, रेल म्यूजियम के पास, हावड़ा-711101 द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा प्रणाली के तहत निविदा सूचना आमंत्रित की जाती है: **कार्य का नाम:** परिणाम आधारित 730 दिनों (02 वर्ष) के लिए पूरे दिन (24 घंटे) कारशेड हावड़ा में ईएमयू रेकों की अंदरूनी शुष्क सफाई और बाहरी गीली सफाई। **निविदा मूल्य:** रु.2,97,27,284.44, **बयाना राशि (ईएमडी):** रु.2,98,600/-, **निविदा कागजात का मूल्य:** रु.0.00, **समापन अवधि:** 730 दिन। **प्रस्ताव की वैधता :** 60 दिन। **निविदा अपलोड करने की तिथि और समय:** 30.06.2026 को 17.24 बजे। **बोली प्रारंभ होने की तिथि:** 07.07.2026, **अंतिम तिथि:** दिनांक 21.07.2026 को 12.00 बजे। **बोली प्रणाली:** दो पैकेट । निविदा कागजात एवं अन्य विवरण वेबसाइट **www.ireps.gov.in** से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा के लिए बोली उपर्युक्त वेबसाइट पर ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से जमा की जाएगी। इस निविदा के लिए मैनुअल प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जाती है एवं कोई मैनुअल प्रस्ताव प्राप्त होने पर इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

HWH-190/2026-27

निविदा सूचना वेबसाइट: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

प्रथम प्रकाशन 1878 भारतमित्र

दुगार्पुर स्टील टाउनशिप स्थित यूनियन कार्यालय में हंगामा, तोड़फोड़, पुलिस तैनात

दुगार्पुर । दुगार्पुर स्टील टाउनशिप के चैतन्य एवेन्यू इलाके में स्थित एक श्रमिक संगठन कार्यालय को लेकर बड़ा राजनीतिक तनाव उत्पन्न हो गया। दुगार्पुर स्टील प्लांट से जुड़े आईएनटीटीयूसी (आईएनटीटीयूसी) मजदूर यूनियन कार्यालय के बाहर भाजपा समर्थकों के प्रदर्शन के दौरान माहौल अचानक उग्र हो गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया और पुलिस को भारी बल के साथ हस्तक्षेप करना पड़ा।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं समर्थक शामिल थे, जिनमें महिलाएं भी अग्रिम पंक्ति में थीं। प्रदर्शनकारियों ने यूनियन कार्यालय पर आरोप लगाया कि यहां के कुछ नेताओं द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से अवैध रूप से धन वसूली की गई है।

आरोप के केंद्र में आईएनटीटीयूसी से जुड़े दो स्थानीय नेताओं के नाम भी सामने आए हैं।

प्रदर्शन के दौरान कार्यकताओं ने यूनियन कार्यालय के भीतर प्रवेश कर जमकर नारेबाजी की और कथित भ्रष्टाचार के विरोध में आक्रोश जताया। आरोप है कि इस दौरान कार्यालय में हल्का नुकसान भी हुआ तथा कुछ सामानों में तोड़फोड़ की गई।

स्थिति बिगड़ते देख प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय पर ताला जड़ दिया और मौके से चले गए। घटना की सूचना मिलते ही दुगार्पुर थाना पुलिस एवं अतिरिक्त बल तुरंत मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया।

पुलिस ने इलाके को घेरकर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस लगातार निगरानी रख रही है। स्थानीय राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, यह पहली बार नहीं है जब इस यूनियन कार्यालय को लेकर विवाद सामने आया हो। कुछ दिन पूर्व भी इसी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जब विभिन्न दलों के समर्थक आमने-सामने आ गए थे। हालिया घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी और अधिक बढ़ गई है। दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे माहौल और अधिक संवेदनशील हो गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है तथा घटनास्थल से प्राप्त जानकारी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

आसनसोल नगर निगम में तीन पार्षदों के इस्तीफों से हलचल

आसनसोल। आसनसोल नगर निगम की राजनीति में शुक्रवार को उस समय महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया, जब तीन पार्षदों ने अपने पदों से इस्तीफा देकर नगर निगम की कार्यप्रणाली और राजनीतिक समीकरणों को लेकर नई चचाओं को जन्म दे दिया। वार्ड संख्या ७२, ७८ और ८४ के निर्वाचित पार्षदों के त्यागपत्र के बाद नगर निगम के भीतर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इन इस्तीफों को स्थानीय राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वार्ड ७८ के पार्षद अशोक रुद्र, वार्ड ७२ के पार्षद एवं बोरो चेयरमैन चैतन्य माझी तथा वार्ड ८४ के पार्षद डॉ. देवाशीष सरकार ने शुक्रवार को अपने-अपने पदों से त्यागपत्र सौंप दिया। इनमें चैतन्य माझी ने पार्षद पद के साथ-साथ बोरो चेयरमैन का पद भी छोड़ दिया, जबकि डॉ. देवाशीष सरकार पहले ही बोरो चेयरमैन पद से इस्तीफा दे चुके थे और अब उन्होंने पार्षद पद से भी त्यागपत्र दे दिया।

डॉ. देवाशीष सरकार ने अपने निर्णय के संबंध में कहा कि उन्होंने कुछ आवश्यक प्रशासनिक कार्यों के पूरा होने तक इस्तीफा नहीं दिया था, ताकि आम नागरिकों के आवश्यक दस्तावेजों से जुड़े कार्य प्रभावित न हों। उन्होंने बताया कि संबंधित कार्य पूरे होने के बाद उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया। उनका कहना था कि वर्तमान परिस्थितियों में वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन इच्छानुसार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए त्यागपत्र देना उचित समझा। वहीं चैतन्य माझी ने अपने इस्तीफे का कारण पूरी तरह व्यक्तिगत बताया।

उन्होंने कहा कि उनकी माता लंबे समय से अस्वस्थ हैं तथा उनके उपचार के लिए उन्हें लगातार बाहर जाना पड़ता है। पिता के निधन के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधि के रूप में अपेक्षित समय और ध्यान जनता को नहीं दे पाने के कारण उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पद छोड़ने के बावजूद वे क्षेत्र की जनता के साथ जुड़े रहेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास करते रहेंगे। नगर निगम के उपमहापौर वसीम उल हक ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक जनप्रतिनिधि को अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है।

आसनसोल-दुगार्पुर पुलिस आयुक्तालय में बड़ी फेरबदल

16 पुलिस अधिकारियों का तबादला

आसनसोल। जनहित को ध्यान में रखते हुए आसनसोल-दुगार्पुर पुलिस आयुक्तालय ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। पुलिस आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार कुल १६ उप-निरीक्षकों और परिवीक्षाधीन उप-निरीक्षकों का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण कर नई तैनाती की गई है। जारी आदेश में सभी स्थानांतरित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना किसी विलंब के अपने नए कार्यस्थल पर योगदान दें। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह फेरबदल जनहित, प्रशासनिक आवश्यकता तथा कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जारी सूची के अनुसार उप-निरीक्षक संजीव दे, जो वर्तमान में दुगार्पुर थाना के थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत थे, उन्हें पुलिस आयुक्तालय के गुप्तचर विभाग के मादक पदार्थ निरोधक शाखा में नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार उप-निरीक्षक मानव घोष, जो आसनसोल दक्षिण पुलिस चौकी के प्रभारी थे, उन्हें दुगार्पुर थाना का थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं उप-निरीक्षक अमर नाथ दास को गुप्तचर विभाग से स्थानांतरित कर रानीगंज थाना भेजा गया है। इसके अलावा उप-निरीक्षक उज्ज्वल कुमार साहा सहित अन्य अधिकारियों का भी विभिन्न थाना क्षेत्रों एवं शाखाओं में स्थानांतरण किया गया है। सभी अधिकारियों को तत्काल अपने नए दायित्व का कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है।

पांडवेश्वर थाना आधुनिक भवन में स्थानांतरित, वर्चुअल उद्घाटन

पांडवेश्वर। आसनसोल-दुगार्पुर पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत पांडवेश्वर थाना अब अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नए भवन से संचालित होगा। शुक्रवार को बीएलआरओ कार्यालय के निकट निर्मित नवनिर्मित थाना भवन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तथा स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में कार्यक्रम गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। नए भवन के संचालन से क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ तथा जनोन्मुखी बनाने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है।

उद्घाटन समारोह के लिए थाना परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों ने औपचारिक उपस्थिति दर्ज कराते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया। नवीन भवन आधुनिक आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित है, जिससे प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। भवन में डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था, सुव्यवस्थित प्रतीक्षालय तथा कार्यालयीन कार्यों के लिए आधुनिक संसाधनों की व्यवस्था की गई है।

वर्चुअल उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सुदृढ़ पुलिस अवसंरचना किसी भी क्षेत्र में प्रभावी कानून-व्यवस्था बनाए रखने की आधारशिला

होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए थाना भवन के संचालन से पुलिसकर्मियों का कार्य वातावरण बेहतर होगा तथा आम नागरिकों को त्वरित और पारदर्शी पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराना अधिक सुगम होगा। कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस आयुक्त डॉ. प्रणव कुमार ने अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायतकर्ता के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक शिकायत पर समयबद्ध और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कानून का पालन करते हुए लोगों का विश्वास जीतना ही पुलिस व्यवस्था की सबसे बड़ी सफलता होगी। इस अवसर पर पांडवेश्वर थाना प्रभारी सुशोभन बनर्जी ने पुलिस आयुक्त का स्वागत किया। कार्यक्रम में पुलिस उपायुक्त, सर्किल इंस्पेक्टर सहित आयुक्तालय के अनेक वरिष्ठ अधिकारी तथा पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने नए भवन को आधुनिक पुलिस व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

आसनसोल गारमेंट एक्सपो में फैशन और व्यापार का संगम

आसनसोल। औद्योगिक नगरी आसनसोल में आयोजित ११वें गारमेंट एक्सपो ने वस्त्र एवं परिधान उद्योग से जुड़े कारोबारियों, उद्यमियों और खरीदारों को एक साझा मंच उपलब्ध कराते हुए व्यापारिक गतिविधियों को नई गति प्रदान की। बिष्णु मामा एवं नीलम ड्रेसेस के तत्वावधान में आयोजित इस तीन दिवसीय आयोजन का शुभारंभ शुक्रवार को गरिमामय वातावरण में हुआ। देश के विभिन्न राज्यों से आए उद्यमियों की भागीदारी ने इस आयोजन को पूर्वी भारत के प्रमुख व्यापारिक आयोजनों में शामिल कर दिया। एक्सपो का उद्घाटन श्री महामंडलेश्वर प्रकाशानंद महाराज ने किया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार की नगर विकास एवं नगर उन्नयन मंत्री अग्निमित्रा पाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। समारोह में समाजसेवी एवं उद्योगपति महेंद्र शर्मा सहित विभिन्न सामाजिक, औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए आयोजकों के प्रयासों की सराहना की और इसे स्थानीय उद्योग के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। आयोजकों के अनुसार इस वर्ष आयोजित एक्सपो में देशभर से १०० से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया है। व्यापार, नवाचार और आधुनिक फैशन की विविधताओं से परिपूर्ण यह आयोजन उद्योग जगत के लिए उपयोगी मंच साबित हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे आयोजन न केवल व्यापारिक संभावनाओं का विस्तार करते हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और औद्योगिक विकास को भी नई ऊर्जा प्रदान करते हैं।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सांस्कृतिक समारोह का समापन

बाराबनी। बाराबनी के दोमोहानी केले जोड़ा बॉयज हाई स्कूल में आयोजित तीन दिवसीय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सांस्कृतिक समारोह का समापन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। समारोह के दौरान बैठकर चित्रांकन प्रतियोगिता, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन एवं योगदान पर भाषण प्रतियोगिता सहित विभिन्न सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समापन समारोह में विद्यार्थियों ने गीत, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आसनसोल बीबी कॉलेज की प्राध्यापिका डॉ. सोमा चक्रवर्ती उपस्थित रहीं। विशिष्ट अतिथियों में बाराबनी सर्किल के अतिरिक्त विद्यालय निरीक्षक अक्षय भट्टाचार्य, विद्यालय के प्रधानाध्यापक मृणाल ज्योति गांगुली, विद्यालय के पूर्व शिक्षक असित बंद्योपाध्याय, समाजसेवी प्रसेनजीत गोड़ाई, सूरत सिंह तथा गौतम पांडे शामिल रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया और ऐसे आयोजनों को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।

जन-जन तक पहुंचे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत

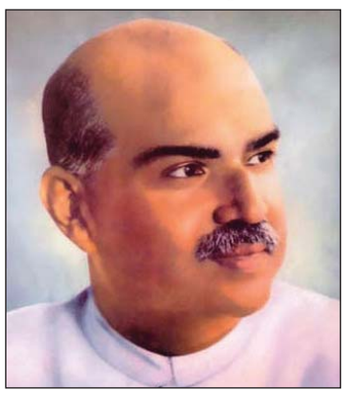

आसनसोल । आसनसोल के प्रख्यात उद्योगपति एवं समाजसेवी सुरेन जालान ने आगामी ६ जुलाई को मनाई जाने वाली डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के संदर्भ में उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को स्मरण किया। सुरेन जालान ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म ६ जुलाई १९०१ को तत्कालीन कलकत्ता में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी देश के विख्यात शिक्षाविद एवं न्यायविद थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डॉ. मुखर्जी ने देश के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया।

बाद में वैचारिक मतभेदों के चलते उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और वर्ष १९५१ में भारतीय जनसंघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके राजनीतिक जीवन का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक चेतना और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करना था।

15 वर्षों से लंबित मांगों को लेकर कम्प्यूटर शिक्षकों का प्रदर्शन

आसनसोल। पश्चिम बंगाल आईसीटी स्कूल कोऑर्डिनेटर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को आसनसोल के एसबी गोराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के समीप जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआई) कार्यालय में विभिन्न मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संगठन के प्रतिनिधियों ने डीआई कार्यालय को ज्ञापन भी सौंपा। संगठन के नेता स्वरूप पान ने बताया कि पिछले १५ वर्षों से सरकारी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है।

आरपीएफ की त्वरित कार्रवाई से मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़

आसनसोल । पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की विभिन्न इकाइयों ने एक साथ कई महत्वपूर्ण कार्रवाइयों को अंजाम दिया, जिसमें यात्रियों के छूटे हुए सामान की बरामदगी से लेकर मानव तस्करी के प्रयास को विफल करने तक की सफलता शामिल रही। इन कार्रवाइयों ने रेल यात्रियों की सुरक्षा और सतर्कता व्यवस्था को और मजबूत किया है।

जानकारी के अनुसार, ०२ जुलाई २०२६ को आरपीएफ की अंडाल ओपन लाइन, दुगार्पुर एवं आसनसोल पश्चिम पोस्ट की टीमों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर रेल परिसर एवं ट्रेनों में यात्रियों द्वारा भूलवश छोड़े गए सामानों को बरामद किया। बरामद सामान की कुल अनुमानित कीमत लगभग १३,७४० आंकी गई। सभी वस्तुओं को आवश्यक सत्यापन के बाद उनके वास्तविक मालिकों को सुरक्षित रूप से सौंप दिया गया।

आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई च्ऑपरेशन अमानतज्ञ के तहत की गई, जिसका उद्देश्य रेलवे परिसर में यात्रियों द्वारा खोई या छूटी हुई संपत्ति को सुरक्षित रूप से वापस लौटाना है। समय पर कार्रवाई के

छोड़ा गया सामान बरामद

कारण यात्रियों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सका। इसी क्रम में ०२ जुलाई २०२६ को ही आरपीएफ जामताड़ा पोस्ट द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध मानव तस्करी के मामले में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी सात नाबालिग लड़कों की अवैध ढंग से तस्करी करने का प्रयास कर रहे थे। आरपीएफ ने तत्परता दिखाते हुए सभी नाबालिगों को सुरक्षित रूप से अपने संरक्षण में लिया और बाद में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें चाइल्डलाइन को सौंप दिया गया।

वहीं, गिरफ्तार आरोपियों को आगे की विधिक कार्रवाई के लिए राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के हवाले कर दिया गया। यह कार्रवाई च्ऑपरेशन एएएचटी के अंतर्गत की गई, जिसका उद्देश्य रेल नेटवर्क के माध्यम से होने वाली मानव तस्करी को रोकना और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त, एक अन्य घटना में पूर्व रेलवे के विभिन्न स्टेशनों और ट्रेनों से कुल ३३,१७० मूल्य के लावारिस बैग एवं अन्य सामान भी बरामद किए गए, जिन्हें सत्यापन के बाद उनके वास्तविक मालिकों को लौटा दिया गया।

निजी कारखाने में श्रमिक की मौत पर प्रदर्शन

दुगार्पुर। दुगार्पुर के कोकओवन थाना क्षेत्र स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में कार्य के दौरान एक ठेका श्रमिक की तबीयत बिगड़ने के बाद हुई मृत्यु से शुक्रवार को कारखाना परिसर में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना के विरोध में मृतक के परिजनों और सहकर्मी श्रमिकों ने कारखाने के मुख्य द्वार के समक्ष प्रदर्शन करते हुए उचित मुआवजा, आश्रित को रोजगार तथा श्रमिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग उठाई।

सूचना मिलते ही कोकओवन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के साथ ही मामले की जांच प्रारंभ कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोकओवन थाना क्षेत्र में डीपीएल प्रशासनिक भवन के समीप स्थित एक निजी कारखाने में ठेका श्रमिक प्रतिदिन की भांति कार्य कर रहा था। इसी दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। सहकर्मियों ने

मुआवजा और आश्रित को रोजगार देने की मांग

उसे तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और बड़ी संख्या में श्रमिक कारखाना परिसर पहुंच गए। घटना से आक्रोशित लोगों ने कारखाने के प्रवेश द्वार के समक्ष शव रखकर विरोध प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मृतक परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। उन्होंने मृतक के आश्रितों को पर्याप्त आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को स्थायी रोजगार तथा सभी वैधानिक श्रमिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए कारखाने के बाहर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। सूचना मिलने पर कोकओवन थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया।

पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को आश्वस्त किया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी तथा कानून के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कारखाना प्रबंधन ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मृतक के परिवार के साथ लगातार संवाद किया जा रहा है। प्रबंधन के अनुसार, नियमानुसार जो भी सहायता और प्रक्रिया निर्धारित है, उसका पालन किया जाएगा।

हालांकि, परिजनों और श्रमिकों की ओर से उठाई गई मांगों पर अंतिम निर्णय बातचीत के बाद ही लिया जाएगा। घटना के बाद श्रमिक संगठनों ने निजी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत ठेका श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर गंभीर प्रश्न उठाए हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मृत्यु के वास्तविक कारणों की पुष्टि होगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है। एहतियात के तौर पर कारखाना परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।

कथित अवैध बालू कारोबार मामले में माखन पाल गिरफ्तार

जामुड़िया। जामुड़िया थाना पुलिस ने एक पुराने आपराधिक मामले में कथित अवैध बालू कारोबार से जुड़े माखन पाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। विधिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद गुरुवार को उन्हें आसनसोल जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारी के बाद जामुड़िया तथा आसपास के क्षेत्रों में इस कार्रवाई को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। वहीं प्रशासन की ओर से अवैध खनन और बालू के अवैध परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को और तेज किए जाने के संकेत भी मिल रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, माखन पाल की गिरफ्तारी एक पूर्व दर्ज

मामले के संबंध में की गई है। बताया गया कि इस मामले में पहले एक बालू से लदा ट्रक जब्त किया गया था, जिसकी जांच के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना अभी जारी है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण: संघ

दोषियों को मिले कठोर दंड

नई दिल्ली । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसके दोषियों को कठोर दंड दिए जाने की मांग की है। संघ ने मंदिर की व्यवस्था संभाल रहे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को याद दिलाया कि हिंदू समाज की स्वाभाविक अपेक्षा है कि व्यवस्था एवं संचालन की कमियां दूर की जाएं।

संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने शुक्रवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि राम मंदिर के दान पात्रों से जमा राशि की चोरी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे समूचे समाज और राम भक्तों की भावना एवं श्रद्धा आहत हुई है। उन्होंने कहा कि संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मान कर गंभीरता से लिया जाए और व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएं। राम मंदिर पर करोड़ों रामभक्तों की आस्था एवं श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहनी चाहिए। वर्तमान की भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी चाहिए। होसबाले ने कहा, ह्यइस दृष्टि से हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि वित्तीय प्रबंधन एवं सुचारू संचालन के लिए पारदर्शी व्यवस्था एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण धार्मिक वातावरण तैयार कर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिंदू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा। उन्होंने कहा कि संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दे।

साथ ही इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करें। सरकार्यवाह होसबाले ने कहा कि राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों रामभक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है।

न्यास के निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है।

जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है।

दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के समर्थकों ने भी रखा एक दिन का उपवास

नई दिल्ली । दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले छह दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक के साथ शुक्रवार को सोशल मीडिया अभियान कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के समर्थकों ने भी एक दिन का उपवास रखा। सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने एक्स पोस्ट में कहा, ह्यहमारी टीम आज सोनम वांगचुक के समर्थन में उपवास कर रही है। उनकी सेहत दिन-ब-दिन बिगड़ रही है और इस समय हमारा सामूहिक समर्थन बहुत जरूरी है। अगर आप भी इस एक दिन के उपवास में शामिल हो रहे हैं, तो कृपया उनका हौसला बढ़ाने के लिए एक वीडियो पोस्ट करें।" दीपके ने कहा कि वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उनके समर्थकों और लद्दाख की जनता ने आज सामूहिक एकजुटता दिखाई है। उनकी टीम और समर्थक आज एक दिवसीय उपवास पर बैठ गए हैं। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को वांगचुक का सुगर लेवल गिरकर 60 तक पहुंच गया और ब्लड प्रेशर भी सामान्य से काफी नीचे आ चुका है, जिससे समर्थकों में भारी चिंता है।

रोशन पंडित हत्याकांड पर पप्पू यादव का बड़ा बयान, बोले- यह सिर्फ जमीन विवाद नहीं, सुनियोजित हत्या

सुपौल । जिले के लक्ष्मीनिया वार्ड-12 में जमीन विवाद को लेकर हुई रोशन कुमार पंडित की हत्या के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। शुक्रवार को पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव मृतक के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की।

इस दौरान उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला केवल जमीन विवाद का नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश के तहत की गई हत्या प्रतीत होती है। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों ने भी उन्हें इसी तरह की आशंका जताई है।

सांसद ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने ड-ीआईजी से बातचीत की है और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की मांग की है। पप्पू यादव ने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि घटनास्थल से महज 25 मीटर की दूरी पर एनडीए सांसद दिलेश्वर कामैत का आवास है। ऐसे में आरोपियों द्वारा इस तरह की वारदात को अंजाम देना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी परिस्थितियों में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।उन्होंने दिवंगत रोशन कुमार पंडित को कोसी क्षेत्र का उभरता सामाजिक चेहरा बताते हुए कहा कि समाज में उनकी अलग पहचान थी और उनकी हत्या से पूरे इलाके में आक्रोश है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि प्रजापति समाज को एनडीए का समर्थक माना जाता है, इसके बावजूद संबंधित जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार से मिलना भी उचित नहीं समझा।

इस दौरान उन्होंने बिहार की कानून-व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में जातीय तनाव का माहौल बन रहा है और अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

रोशन कुमार पंडित हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पप्पू यादव ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एस-ाआईटी) गठित करने तथा स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की।

एनर्जी ड्रिंक के दावों पर एफएसएसएआई सख्त, कई बेवरेज ब्रांड्स को नोटिस

नई दिल्ली । भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खुद को 'एनर्जी ड्रिंक' बताने वाले कई बेवरेज ब्रांड्स को मिसब्रांडिंग और भ्रामक दावों के आरोप में नोटिस जारी किया है। एफएसएसएआई के अनुसार, इन उत्पादों की ब्रांडिंग और प्रचार-प्रसार में ऐसे दावे किए गए, जो खाद्य सुरक्षा एवं लेबलिंग नियमों के अनुरूप नहीं पाए गए। इनमें रेड बुल एनर्जी ड्रिंक, स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, मॉन्स्टर एनर्जी, कैंपा गोल्ड बूस्ट, एड्रेनालाइन रश, हैल एनर्जी शामिल है। नियामक ने संबंधित कंपनियों से जवाब मांगा है और निर्देश दिया है कि वे भ्रामक दावों तथा गलत ब्रांडिंग को तुरंत सुधारें। नियामक ने इन कंपनियों की मार्केटिंग, लेबलिंग और प्रचार पर कड़ी आपत्ति जताई है। नोटिस में कहा गया है कि गैर-मान्यता प्राप्त शब्दः भारत में 'एनर्जी ड्रिंक' नाम की कोई आधिकारिक खाद्य श्रेणी मौजूद नहीं है। भ्रामक दावे खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत भोजन या पेय पदार्थों पर दिमाग और शरीर में स्फूर्ति, फोकस बढ़ाना , ऊर्जा स्तर को बूस्ट करनाश्र या आम कमजोरी दूर करना जैसे चिकित्सीय या कार्यात्मक दावे करना प्रतिबंधित है।

विदेशी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार

अररिया । एसएसबी 56वीं वाहिनी की बी समवाय डुबा टोला की विशेष गश्ती टीम ने शुक्रवार को 87 बोतल नेपाल से तस्करी कर ला रहे बाइक सवार तस्कर को गिरफ्तार किया। एसएसबी ने यह कार्रवाई आमगाछी के कुकुरवा गांव में सीमा स्तंभ संख्या 174 के नजदीक की।

एसएसबी ने अलग अलग ब्रांडों के नेपाल निर्मित विदेशी शराब के साथ हीरो ग्लैमर बाइक संख्या बीआर38एस 1132 और एक मोबाइल फोन जब्त किया।

मामले में एसएसबी ने तस्कर सोनमणी गुदाम के वार्ड संख्या पांच कुकुरवा निवासी 22 वर्षीय तस्कर दिलखुश कुमार यादव पिता सत्यनारायण यादव को गिरफ्तार किया। जो नेपाल से भारत शराब को बाइक पर लोड कर तस्करी कर ला रहा था।

जापानी कंपनियां ओडिशा में करेंगी 67,000 करोड़ का निवेश

भुवनेश्वर । ओडिशा सरकार ने जापान के साथ अपनी रणनीतिक आर्थिक साझेदारी को मजबूत करते हुए जापान की आईएचआई कॉर्पोरेशन और एसीएमई ग्रुप के साथ 67,000 करोड़ रुपये के निवेश संबंधी महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस निवेश से राज्य में हरित ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण और औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। यह समझौता राज्य सरकार द्वारा आयोजित 'इंटरैक्शन विद जापानी बिजनेस डेलीगेट्स' कार्यक्रम के दौरान हुआ। प्रस्तावित निवेश से करीब 7,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है। राज्य सरकार का मानना है कि यह साझेदारी ओडिशा को स्वच्छ ऊर्जा और वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगी। समझौते के तहत गोपालपुर-टाटा विशेष आर्थिक क्षेत्र में 0.4 एमटीपीए क्षमता का ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें 20,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और लगभग 3,400 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा, इस परियोजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये की लागत से जेटी-लेस फ्लोटिंग टर्मिनल का निर्माण भी किया जाएगा। वहीं पारादीप में 0.8 एमटीपीए क्षमता का ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें 34,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और करीब 3,600 रोजगार सृजित होंगे। इसके अतिरिक्त 12,000 करोड़ रुपये की लागत से ग्रीन मेथनॉल परियोजना भी विकसित की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उद्योग एवं कौशल विकास मंत्री संपद चंद्र स्वाईं, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विश्व बैंक समूह, जापान दूतावास तथा कई प्रमुख जापानी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि जापान भारत का सबसे भरोसेमंद विकास और निवेश साझेदार रहा है। उन्होंने कहा कि यह समझौता ओडिशा के औद्योगिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा और 'समृद्ध ओडिशा-2036' तथा 'विकसित भारत-2047' के लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उद्योग मंत्री संपद चंद्र स्वाईं ने कहा कि ओडिशा अपनी निवेश-अनुकूल नीतियों, मजबूत आधारभूत संरचना और पारदर्शी प्रशासन के कारण वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बन चुका है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार सभी निवेश परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए हरसंभव सहयोग देगी।

आईएचआई कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हिरोशी इदे ने ओडिशा की रणनीतिक स्थिति, औद्योगिक आधार और प्राकृतिक संसाधनों की सराहना की। वहीं एसीएमई ग्रुप के संस्थापक एवं अध्यक्ष मनोज उपाध्याय ने कहा कि यह साझेदारी भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा देने के साथ अत्याधुनिक तकनीक और परियोजना विकास विशेषज्ञता को एक मंच पर लाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार, यह समझौता ओडिशा और जापान के बीच आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई देगा तथा हरित हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, एयरोस्पेस, शिपबिल्डिंग, लॉजिस्टिक्स, इस्पात और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भविष्य के निवेश का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

यह समझौता ओडिशा और जापान के बीच बढ़ती आर्थिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जा रहा है, जिससे राज्य में स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक उद्योगों के विकास को गति मिलने के साथ-साथ एमएसएमई, सहायक उद्योगों, स्थानीय उद्यमों और युवाओं के लिए रोजगार एवं विकास के नए अवसर सृजित होंगे।

इजराइल ने आयरन डोम के अपग्रेडेड सिस्टम के तौर पर 'आयरन बीम' लेजर का किया टेस्ट

मॉस्को/तेल अवीव । इजराइल ने अपने बहुस्तरीय एयर डिफेंस नेटवर्क को और मजबूत करते हुए अपग्रेडेड 'आयरन डोम' सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इजराइली रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि परीक्षण के दौरान पहली बार 'आयरन बीम' लेजर सिस्टम का सफल ऑपरेशनल इंटीग्रेशन भी प्रदर्शित किया गया, जिससे एक साथ कई तरह के हवाई हमलों का मुकाबला करने की क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास व अन्य मीडिया रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि यह परीक्षण इजराइल मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन (आईएमडीओ), रक्षा मंत्रालय के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डायरेक्टरेट (डीडीआर और डी) और राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स के संयुक्त प्रयास से किया गया। हालांकि, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए परीक्षण से जुड़ी तकनीकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। मंत्रालय ने कहा कि नए अपग्रेड से रॉकेट, क्रूज मिसाइल और मानव रहित विमान (यूएवी) जैसे मौजूदा और भविष्य के खतरों के खिलाफ सिस्टम की क्षमता और प्रभावशीलता बढ़ी है। इसके अलावा, तेज और बड़ी संख्या में होने वाले हमलों से निपटने के लिए सिस्टम में कई तकनीकी सुधार किए गए हैं। बयान में कहा गया कि परीक्षण के दौरान प्रदर्शित नई क्षमताएं विभिन्न प्रकार के हमलों का एक साथ मुकाबला करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हैं। विशेष रूप से 'आयरन बीम' लेजर को 'आयरन डोम' के बैटल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया, जिससे भविष्य में ऑपरेशनल तैनाती का रास्ता और मजबूत होगा।

इस इंटीग्रेशन के बाद कमांडर खतरे की प्रकृति, सिस्टम की उपलब्धता और लागत के आधार पर मिसाइल या लेजर इंटरसेप्शन के बीच तुरंत निर्णय ले सकेंगे। जहां 'तमिर' इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लगभग 50,000 डॉलर है, वहीं 'आयरन बीम' के लेजर शॉट की लागत महज कुछ डॉलर बताई जाती है, जिससे एयर डिफेंस संचालन अधिक किफायती हो सकता है।

पाकिस्तान में बस खाई में गिरी, कम से कम 40 यात्रियों की मौत

इस्लामाबाद । पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत में आज क्वेटा से पेशावर जा रही बस झोब और डेरा इस्माइल खान के बीच डाना सर इलाके में गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार यह हाल के वर्षों में इस इलाके की सबसे घातक सड़क दुर्घटना है। बलोचिस्तान के मुख्यमंत्री के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने हादसे की पुष्टि की है। जियो न्यूज और दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, बलोचिस्तान के मुख्यमंत्री के प्रवक्ता रिंद ने कहा कि जिला अधिकारी, बचाव एजेंसियां और अन्य संबंधित विभाग राहत कार्य में जुटे हैं। जिला उपायुक्त शेरानी वली काकर ने कहा कि ऊबड़-खाबड़ इलाका होने के कारण बचाव दलों को दुर्घटनास्थल तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि बलोचिस्तान के नजदीकी अस्पतालों में आपातकाल घोषित किया है। अधिकारियों ने बताया कि बस के ब्रेक फेल होने की आशंका है। मृतकों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं।

Nagaland State Lotteries
DEAR
VICTORY FRIDAY WEEKLY LOTTERY
01:00 PM
Draw No:35 Price ₹7/- Draw Date on:03/07/26
1st Prize Amount For Winner ₹1 Crore + For Seller ₹5 Lakhs/- 77H 50938
Cons. Prize Amount For Winner ₹ 1000/- + For Seller ₹ 500/- 50938
(All Remaining Serial & Series of 1st Prize No.)
2nd Prize Amount For Winner ₹ 10,000/- + For Seller ₹ 500/-
00723 11598 27208 33953 45444
58859 90200 98575 99238 99584
3rd Prize Amount For Winner ₹ 500/- + For Seller ₹ 50/-
1455 3974 4418 4786 4955 5097 5494 7055 7323 7373
4th Prize Amount For Winner ₹ 250/- + For Seller ₹ 20/-
1167 1252 1706 2446 3608 5639 6338 6623 6761 8907
5th Prize Amount For Winner ₹ 120/- + For Seller ₹ 10/-
0008 0863 1925 2856 4160 5117 6038 7196 8553 9327
0068 0990 2028 2969 4217 5199 6213 7200 8629 9376
0232 1206 2146 3119 4262 5235 6323 7353 8696 9378
0324 1239 2174 3238 4308 5419 6403 7523 8738 9455
0457 1490 2309 3320 4407 5552 6406 7661 8771 9679
0497 1587 2350 3365 4897 5553 6668 7713 9093 9740
0545 1608 2425 3484 4908 5970 6727 8051 9195 9752
0670 1609 2534 4002 4909 5995 6762 8303 9272 9794
0714 1673 2612 4116 4965 6003 6897 8406 9294 9878
0798 1692 2760 4155 5029 6005 7173 8474 9296 9939
01:00 PM
Issued by : Director, Nagaland State Lotteries, Kohima
Watch Live Draw On : YouTube
nagalandlotteries.com/livedraw

Sikkim State Lotteries
DEAR
CROWN FRIDAY WEEKLY LOTTERY
06:00 PM
Draw No : 40 Price ₹7/- Draw Date on : 03/07/26
1st Prize Amount For Winner ₹1 Crore + For Seller ₹5 Lakhs/- 99B 15112
SOLD BY : SELLER - CHITTARANJAN SAHA - RAGHUNATHGANJ & SUB-STOCKIST - CHANDRA LOTTERY AGENCY - RAGHUNATHGANJ
Cons. Prize Amount For Winner ₹ 1000/- + For Seller ₹ 500/- 15112
(All Remaining Serial & Series of 1st Prize No.)
2nd Prize Amount For Winner ₹ 10,000/- + For Seller ₹ 500/-
19968 23877 35589 50807 51463
68759 70539 81753 95662 97917
3rd Prize Amount For Winner ₹ 500/- + For Seller ₹ 50/-
1204 3100 4402 4686 5181 5615 5636 7568 8316 8377
4th Prize Amount For Winner ₹ 250/- + For Seller ₹ 20/-
0478 1510 2839 2843 3137 3243 5642 8422 8600 8627
5th Prize Amount For Winner ₹ 120/- + For Seller ₹ 10/-
0057 0891 1798 3098 3735 5215 6022 6925 7628 8836
0169 1202 2214 3188 4182 5385 6155 6946 7944 8840
0174 1210 2396 3253 4202 5397 6330 6958 8214 9032
0223 1352 2532 3310 4294 5479 6461 7104 8312 9095
0269 1479 2595 3319 4461 5514 6502 7238 8387 9167
0277 1522 2696 3455 4512 5536 6721 7252 8399 9350
0394 1638 2887 3484 4536 5537 6783 7299 8433 9526
0448 1680 2910 3491 4614 5586 6822 7410 8545 9784
0621 1777 2953 3665 4695 5793 6866 7499 8611 9931
0855 1786 3017 3690 4828 5978 6912 7599 8662 9981
06:00 PM
Issued by :The Principal Director, Sikkim State Lotteries, Gangtok
Watch Live Draw On : YouTube
sikkimlotteries.com/livedraw

Nagaland State Lotteries
DEAR
HORIZON FRIDAY WEEKLY LOTTERY
08:00 PM
Draw No: 35 Price ₹7/- Draw Date on: 03/07/26
1st Prize Amount For Winner ₹1 Crore + For Seller ₹5 Lakhs/- 66A 34941
SOLD BY : SELLER - BIJAY DAS - DEBINAGAR & SUB-STOCKIST - GHOSH AGENCY - MAHARAJAHAT
Cons. Prize Amount For Winner ₹ 1000/- + For Seller ₹ 500/- 34941
(All Remaining Serial & Series of 1st Prize No.)
2nd Prize Amount For Winner ₹ 10,000/- + For Seller ₹ 500/-
02865 04401 16299 30031 32046
34288 38790 52452 72258 93755
3rd Prize Amount For Winner ₹ 500/- + For Seller ₹ 50/-
1050 1934 2321 2783 4178 4298 5156 6310 6527 8119
4th Prize Amount For Winner ₹ 250/- + For Seller ₹ 20/-
0481 1032 1445 3990 4540 6408 6424 6539 7082 7981
5th Prize Amount For Winner ₹ 120/- + For Seller ₹ 10/-
0049 0626 2328 3316 4495 5218 6130 7631 8494 9269
0113 1163 2355 3438 4549 5257 6146 7966 8550 9363
0139 1264 2498 3669 4596 5265 6332 8058 8587 9420
0239 1311 2646 3681 4676 5271 6422 8205 8623 9434
0319 1354 2649 3761 4850 5433 6842 8238 8781 9502
0368 1485 2681 3978 4940 5552 6873 8294 8829 9516
0402 1643 2771 3994 5123 5713 7087 8337 8849 9670
0503 1898 3166 4045 5127 5829 7354 8381 8956 9744
0517 1982 3295 4129 5159 5875 7408 8389 9016 9810
0604 2021 3305 4177 5172 5962 7605 8416 9245 9924
08:00 PM
Issued by : Director, Nagaland State Lotteries, Kohima
Watch Live Draw On : YouTube
nagalandlotteries.com/livedraw
* TDS 2% UNDER SECTION 393(3) IT ACT 2025 SHALL BE DEDUCTED ON SELLERS PRIZE AMOUNT W.E.F. 01.04.2026
PLEASE CHECK THE RESULTS WITH RELEVENT OFFICIAL GOVERNMENT GAZATTE

Registered No. KOL. RMS/350/2015-17 प्रथम प्रकाशन 1878 भारतमित्र

2036 ओलंपिक के लिए भारत का रोडमैप तैयार, नए चयन नियमों के साथ आगे बढ़ेगी दावेदारी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) की नई मेजबान चयन प्रक्रिया को लेकर भी आश्वस्त नजर आ रहा है। भारतीय पक्ष का कहना है कि वह विभिन्न माध्यमों से आईओसी के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखेगा।भारत ने 2024 में अहमदाबाद में 2036 ओलंपिक आयोजित करने की मंशा जताते हुए आईओसी को औपचारिक 'लेटर ऑफ इंटेंट' सौंपा था। हालांकि, 2025 में आईओसी की नई अध्यक्ष किर्स्टी कोवेंट्री ने मेजबान चयन प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक कार्य समूह गठित किया, जिसके बाद पूरी प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था।

हाल ही में आईओसी सत्र में नई चयन

प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत 2036 ओलंपिक के मेजबान का फैसला वर्ष 2029 के मध्य में किया जाएगा। भारत की ओर से इस पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) गुजरात सरकार के सहयोग से करेगा।

विभिन्न माध्यमों से मजबूत करेगा दावा

एक वरिष्ठ सूत्र ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि सरकार सीधे आईओसी सदस्यों से संपर्क नहीं कर सकती, लेकिन कई अन्य माध्यम मौजूद हैं, जिनके जरिए भारत अपने दावे को मजबूत करेगा। हालांकि उन्होंने इन माध्यमों का खुलासा नहीं किया।

मानसून सत्र में पेश होगा संशोधित राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग बिल

केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में संशोधित राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इस संशोधन का उद्देश्य खिलाड़ियों तक प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी और आपूर्ति करने वालों के खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधान लागू करना है।

पांच साल तक की जेल का प्रावधान

संशोधित बिल में खिलाड़ियों को प्रतिबंधित पदार्थ उपलब्ध कराने या उनकी तस्करी करने वालों के लिए अधिकतम पांच साल की जेल का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, यदि कोई डॉक्टर या चिकित्सा विशेषज्ञ जानबूझकर प्रतिबंधित दवाएं लिखता है, तो उसे भी इस कानून के दायरे में लाया जाएगा। इस संशोधित विधेयक पर 18 जून तक सार्वजनिक सुझाव मांगे गए थे और अब परामर्श प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें इसे पेश किए जाने की संभावना है।

सरकार क्यों ला रही है यह संशोधन?

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया लगातार यह कहते रहे हैं कि प्रतिबंधित दवाओं की संगठित आपूर्ति को अपराध घोषित करना समय की जरूरत है। पिछले तीन वर्षों से भारत विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी (वाडा) की डोपिंग उल्लंघन करने वाले देशों की सूची में शीर्ष पर रहा है। इसी तरह का प्रस्ताव 2018 में भी लाया गया था, जिसमें दोषियों के लिए चार साल की जेल और दो लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान था। हालांकि, 2022 में पारित कानून से इन प्रावधानों को हटा दिया गया था, क्योंकि सरकार ने उस समय दंडात्मक कानून की बजाय रोकथाम आधारित कानून को प्राथमिकता दी थी। अब संशोधित बिल के जरिए फिर से कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू करने की तैयारी की जा रही है।

21वीं वरीयता प्राप्त मैरी ने इटली की टायरा को हराया

बोजकोवा और नवारो तीसरे दौर में क्रेजिकोवा ने एंड्रीवा को किया बाहर

नई दिल्ली, एजेंसी। विंबलडन 2026 के महिला एकल मुकाबलों में चेक गणराज्य की मैरी बोजकोवा और अमेरिका की एम्मा नवारो ने दूसरे दौर में जीत दर्ज कर तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। वहीं, बुधवार को खेले गए एक बड़े उलटफेर में बारबोरा क्रेजिकोवा ने पांचवीं वरीयता प्राप्त मिर्रा एंड्रीवा को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया।

सीधे सेटों में दर्ज की जीत

21वीं वरीयता प्राप्त मैरी बोजकोवा ने इटली की क्वालीफायर टायरा कैटरिना ग्रांट को 7-5, 6-3 से हराया। पहले सेट में शुरुआती ब्रेक गंवाने के बावजूद बोजकोवा ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। वह तीसरी बार विंबलडन के तीसरे दौर में पहुंची हैं। 2022 में वह यहां क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थीं।

अब सैमसोनोवा से होगी टक्कर

घास के कोर्ट पर इस सीजन बोजकोवा की यह सातवीं जीत है। तीसरे दौर में उनका सामना ल्यूडमिला सैमसोनोवा से होगा। सैमसोनोवा ने 15वीं वरीयता प्राप्त डायना श्नाइडर को 6-4, 4-6, 6-2 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई।

नवारो ने शानदार वापसी से जीता मुकाबला

अमेरिका की एम्मा नवारो ने पहला सेट गंवाने के बाद दमदार वापसी करते हुए ओक्साना सेलेखमेतयेवा को 3-6, 6-4, 6-1 से मात दी। नवारो लगातार तीसरे साल विंबलडन के तीसरे दौर में पहुंची हैं। वह 2024 में क्वार्टर फाइनल और पिछले साल चौथे दौर तक पहुंची थीं।

तीसरे दौर में किससे होगा सामना

नवारो ने अपने पिछले 18 टूर-स्तरीय मुकाबलों में 14वीं जीत दर्ज की है। अब उनका मुकाबला 12वीं वरीयता प्राप्त मार्टा कोस्त्युक और अन्ना ब्लिंकोवा के बीच होने वाले मैच की विजेता से होगा।

क्रेजिकोवा ने एंड्रीवा को किया बाहर

बुधवार को खेले गए दूसरे दौर के सबसे चर्चित मुकाबले में दो बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन बारबोरा क्रेजिकोवा ने मिर्रा एंड्रीवा को 4-6, 7-5, 6-4 से हराकर शानदार वापसी की। जीत दर्ज करने के लिए उन्हें सात मैच प्वाइंट लगाने पड़े।

ऑल-चेक मुकाबला होगा तीसरे दौर में

क्रेजिकोवा अब तीसरे दौर में अपनी हमवतन निकोला बारटुनकोवा से भिड़ेंगी। बारटुनकोवा ने 32वीं वरीयता प्राप्त कैटरीना सिनियाकोवा को 6-2, 6-4 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। एंड्रीवा के खिलाफ यह क्रेजिकोवा की पांच मुकाबलों में दूसरी जीत रही।

पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी

प्रथम पुरस्कार विजेता के लिए राशि ₹1.50 करोड़ गारंटीड

टिकट मूल्य ₹200

ड्रॉ दिनांक 04.07.2026 6 PM Onwards

SELLER Prize Amount : ₹10 LAKHS

SUB-STOCKIST Prize Amount : ₹5 LAKHS

प्रथम पुरस्कार केवल बिक्री की गयी टिकटों में से ही निकाली जायेगी।

LIVE STREAMING www.punjabilotteries.com/livedraw

द्वितीय पुरस्कार राशि विजेताओं के लिए ₹20 लाख (₹10 Lakhs x 2 Prizes)

तृतीय पुरस्कार राशि विजेताओं के लिए ₹10 लाख (₹5 Lakhs x 2 Prizes)

Seller Prize Amount : ₹1,00,000 Sub-Stockist Prize Amount : ₹50,000

Seller Prize Amount : ₹50,000 Sub-Stockist Prize Amount : ₹20,000

कई अन्य आकर्षक पुरस्कार जीतें

Rank	No. of Prizes	Prize Amount for Winners ₹	Prize Amount for Sellers ₹	Prize Amount for Sub-Stockist ₹	Method of Draw
1	1	1,50,00,000	10,00,000	5,00,000	One Complete Number of 6 Digits shall be drawn Either from Series A or B, If number falls from unsold tickets, then machine shall be re-operated till the prize is drawn from sold tickets.
2	2	10,00,000	1,00,000	50,000	Two Complete Number of 6 Digit Shall be Drawn along with Series. One from A Series & One from B Series
3	2	5,00,000	50,000	20,000	Two Complete Number of 6 Digit Shall be Drawn along with Series. One from A Series & One from B Series
4	60	9,000	900	100	Ten Numbers of 5 Digits Shall be Drawn. (Last 5 Digits of Ticket Numbers will be considered, Common to All Series)
5	120	8,000	800	50	Two Numbers of 4 Digits Shall be Drawn. (Last 4 Digits of Ticket Numbers will be considered, Common to All Series)
6	120	6,000	600	50	Two Numbers of 4 Digits Shall be Drawn. (Last 4 Digits of Ticket Numbers will be considered, Common to All Series)
7	300	4,000	400	30	Five Numbers of 4 Digits Shall be Drawn. (Last 4 Digits of Ticket Numbers will be considered, Common to All Series)
8	300	2,000	200	20	Five Numbers of 4 Digits Shall be Drawn. (Last 4 Digits of Ticket Numbers will be considered, Common to All Series)
9	30,000	300	30	10	Five Hundred Numbers of 4 Digits Shall be Drawn. (Last 4 Digits of Ticket Numbers will be considered, Common to All Series)

★ Prize Amount for Sellers & Sub-Stockists above ₹10,000 should be claimed from Government only
★TDS 2% UNDER SECTION 393(3) IT ACT 2025 SHALL BE DEDUCTED ON SELLERS PRIZE AMOUNT W.E.F. 01.04.2026
Issued by : Directorate of Small Savings, Banking and Lotteries, Punjab

₹ 1.50 करोड़ के हालिया विजेता

DEAR 200 MONTHLY — Mr. KAPIL DEV, Draw Date: 07.03.2026, Ticket No. 794994
DEAR 200 MONTHLY — Mrs. VAISHALI TUSHAR DESHMUKH, Draw Date: 08.03.2025, Ticket No. 545595
DEAR 200 MONTHLY — Mr. HARJIT SINGH, Draw Date: 04.02.2025, Ticket No. 746535
DEAR 200 MONTHLY — Mr. BIBHUTI KUMAR RAI, Draw Date: 07.01.2025, Ticket No. 308196
DEAR 200 MONTHLY — Mr. MANGAL SINGH, Draw Date: 03.12.2024, Ticket No. 347063

पूछताछ के लिए, कॉल करें (टोल फ्री) : 1800 103 6711 (पश्चिम बंगाल) टिकट सभी लॉटरी काउन्टरों पर उपलब्ध हैं

सबा करीम ने बताया क्यों है पूरा भरोसा

वैभव को 145-150 किमी/घंटे की गेंदें भी नहीं रोक पाएंगी

नई दिल्ली। आईपीएल 2026 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित करने वाले युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर सबा करीम ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी में कई नए शॉट्स जोड़े हैं और अब वह 145-150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंदों समेत हर तरह की गेंदबाजी का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सबा करीम ने यह भी खुलासा किया कि राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ को पहले से ही पूरा भरोसा था कि वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में अपने दूसरे सीजन के दबाव में नहीं टूटेंगे और भविष्य में वह भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलेंगे।

सबा करीम से विक्रम राठौड़ ने कहा था, ''सबा, बस इंतजार करो और देखो। मुझे लगता है कि वह किसी भी तरह की गेंद का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।'' ब्रॉडकॉस्टर के 'गेम प्लान' पर बात करते हुए एक्सपर्ट सबा करीम ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी बहुत तेजी से गेंदबाजों को को पढ़ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। अब दुनिया इंटरनेशनल क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का इंतजार कर रही है।

सबा करीम ने कहा, ''वैभव सूर्यवंशी ने 2026 में अपने शॉट्स की रेंज को काफी बढ़ाया है और वह तैयार दिखते हैं।'' सबा करीम ने विस्तार से बताते हुए कहा, ''यह वैभव की बल्लेबाजी की सबसे अच्छी खूबी है। उन्हें बहुत जल्दी पता चल जाता है कि गेंदबाज उन्हें कहां टारगेट कर सकते हैं। वह कुछ गेंदों में ही यह समझ लेते हैं कि क्या उनके पास उन गेंदों पर रन बनाने के लिए सही शॉट्स हैं या नहीं और उसी हिसाब से तैयारी करते हैं।'' सबा करीम ने कहा, ''उन्होंने इसी तरह की तैयारी की है, इसीलिए इस साल हमने उन्हें छोटी गेंदों पर 'अपर कट' खेलते, मजबूत बेस के साथ 'कवर' की तरफ शॉट मारते, 'लॉन्ग ऑफ' और 'कवर' के ऊपर से शॉट खेलते और 'इनसाइड-आउट' शॉट्स खेलते देखा है। उन्होंने अपने स्कोरिंग शॉट्स में जो ये सभी नए शॉट्स जोड़े हैं, उनका मतलब है कि अब चाहे हालात कैसे भी हों या गेंदबाजी कैसी भी हो, वह तैयार हैं।'' सबा करीम का मानना है कि बेखौफ होकर ऑफ-साइड पर शॉट खेलना उनके हुनर और तूफानी अंदाज को बनाए रखने की काबिलियत को दिखाता है।

इंटर-स्कूल फुटबॉल को बढ़ावा

ओरिएंटल कप 2026 में ट्रॉफी के साथ छात्रवृत्ति भी

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर के इंटर-स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट ओरिएंटल कप ने इस बार युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। चौथे संस्करण में पहली बार 10 छात्र-खिलाड़ियों के लिए 2.5 लाख रुपये की छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इसके साथ ही टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि भी दोगुने से अधिक बढ़ा दी गई है। सात से 16 जुलाई तक नई दिल्ली के डॉ. आंबेडकर स्टेडियम में होने वाले इस टूर्नामेंट में 45 से अधिक स्कूलों की टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट में करीब 1500 खिलाड़ियों के मैदान में उतरने की उम्मीद है। छात्रवृत्ति शुरू करने का उद्देश्य केवल विजेता टीमों को सम्मानित करना नहीं, बल्कि उन खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ाना है जिनमें भविष्य की संभावनाएं हैं। टूर्नामेंट के बाद भी युवा खिलाड़ियों को फुटबॉल खेलना जारी रखने के लिए बढ़ावा मिले। ओरिएंटल कप के संस्थापक फरीद बख्शी ने जनसत्ता को बताया कि टूर्नामेंट का मकसद हर साल युवा खिलाड़ियों के लिए नए अवसर तैयार करना है। उनके अनुसार, छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का फैसला प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने की सोच का हिस्सा है।

डियर साप्ताहिक लॉटरी खड़गपुर निवासी ने ₹1 करोड़ जीते

खड़गपुर, पश्चिम बंगाल से श्री कंचन बारन पाल ने **14.04.2026** को सम्पन्न हुए डियर साप्ताहिक लॉटरी के ड्रॉ में प्रथम पुरस्कार के तौर पर ₹ 1 करोड़ जीते हैं। उनकी विजेता टिकट का नंबर **87E 83363** है। उन्होंने सिक्किम स्टेट लॉटरीज के पास प्राइज क्लेम फॉर्म के साथ अपनी पुरस्कार-विजेता टिकट जमा कर दी है। "अत्यंत कृतज्ञता के साथ, मैं डियर लॉटरी और सिक्किम स्टेट लॉटरीज के प्रति आम लोगों को ऐसा एक आश्चर्यजनक अवसर देने के लिए जिसमें वे बगैर किसी परेशानी के अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। यह पूरे परिवार को अद्भुत खुशियां देती हैं, क्योंकि एक करोड़ रुपए जीतना एक आसान काम नहीं है," विजेता ने कहा।

*विजेता का विवरण सरकारी वेबसाइट से लिया गया है।

स्वत्वाधिकारी एल.एस. पब्लिकेशन्स प्रा. लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक ममता वाजयपेयी द्वारा 4,केनाल वेस्ट रोड, कोलकाता -15 से मुद्रित एवं प्रकाशित। प्रेरक संपादकः राजेन्द्र नारायण वाजपेयी । **संपादक : रितेश वाजपेयी।**
Phone: 2236-1572,4800 9234, E-mail-bharatmitral@gmail.com, Fax No.-033-3315-1533, **हवाई शुल्कः** अगरतला 6 रुपये,गुवाहाटी 5 रुपये, पोर्टब्लेयर 8 रुपये। प्रकाशन से उत्पन्न सभी विवाद कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन